नई दिल्ली
12 जुलाई, 2026 शनिवार
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 101
RNI No. DELMUL/2012/47011
अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com
Email : timesofpedia@gmail.com

31 साल बाद विंबलडन फाइनल में पहुंचने वाले पहले जर्मन खिलाड़ी बने एलेक्जेंडर जेवरेव 07

संक्षिप्त वार्ता

ब्रिटेन की पूर्व सांसद एन विडिकॉम्ब की घर में संदिग्ध हत्या

वेब वार्ता, लंदन। ब्रिटेन की जानी-मानी राजनीतिज्ञ एन विडिकॉम्ब की उनके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या किए जाने का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। डेवोन के डार्टमूर स्थित उनके घर पर विडिकॉम्ब का शव बरामद हुआ जिस पर गंभीर चोटों के निशान थे, जिसके बाद राजनीतिक हलके में शोक और आक्रोश देखा गया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 26 साल के ब्रिटिश नागरिक को गिरफ्तार किया है।

डेवोन और कॉर्नवाल पुलिस के मुताबिक गुरुवार सुबह करीब 11:40 बजे डेवोन के हेयटोर स्थित उनके घर विडिकॉम्ब्स रेस्ट में उनका शव मिला। शुरूआती जांच के बाद पुलिस ने न्यूटन एबट इलाके से एक संदिग्ध युवक को दबोच लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। एक्सेटर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असिस्टेंट चीफ कांस्टेबल मैट लॉन्गमैन ने स्पष्ट किया कि शुरूआती जांच किसी भी प्रकार के आतंकवादी या राजनीतिक मकसद को खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जांच अभी शुरूआती चरण में है और पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर काम कर रही है।

दुबई से लखनऊ आ रहे विमान से टकराया पक्षी

वेब वार्ता, लखनऊ। लखनऊ आ रहे दुबई के विमान से शनिवार सुबह पक्षी टकरा गया। यह घटना तब हुई जब विमान लखनऊ के करीब पहुंच गया था। पक्षी के टकराते ही पायलट ने विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। विमान में 163 यात्री सवार थे। विमान 40 मिनट की देरी से लखनऊ पहुंचने वाला था। पक्षी के टकराते ही पायलट ने विमान के लिए आपातकाल में रनवे पर जगह मांगी। विमान सुबह 7:13 बजे सकुशल लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। करीब 6 घंटे से दोपहर डेढ़ बजे तक यह विमान एयरपोर्ट के पार्किंग वे में ही खड़ा रहा।

सीएम सम्राट चौधरी के हेलिकाप्टर में आयी तकनीकी खराबी

वेब वार्ता, वैशाली। बिहार के वैशाली जिले से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हेलीकॉप्टर के साथ आसमान में बड़ा हादसा होते होते बचा. वैशाली के अक्षयवट राय स्टेडियम में उस समय अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया जब मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के तुरंत बाद हवा में ही लटक गया. आलम यह था कि करीब 5 से 10 मिनट तक यह हेलीकॉप्टर आसमान में बीच मझधार में झूलता रहा. इस नजारे को देखकर मैदान पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों से लेकर आम जनता तक के हाथ पैर फूल गए और चारों तरफ हड़कंप मच गया.

दतिया में धारा 163 लागू, नरोत्तम मिश्रा बोले- पेट्रोल डालने वाला काम न करें कार्यकर्ता

वेब वार्ता, दतिया। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उप चुनाव होना है. उप चुनाव से पहले सीट पर बवाल मच गया है. भाजपा ने आशुतोष तिवारी को यहां से अपना उम्मीदवार घोषित किया है. भाजपा से टिकट पाने की उम्मीद में बैठे भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया है, जिस वजह से उनके समर्थक भड़क गए. मिश्रा के समर्थकों ने शहर भर में प्रदर्शन किया, जिसने हिंसक प्रदर्शन का रूप ले लिया.

अब अनुब्रत मंडल ने छोड़ा दीदी का साथ

वेब वार्ता, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के ऋतब्रत बनर्जी वाले गुट ने अपनी जिला कमिटी और अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है। इस घोषणा में सबसे हैरान करने वाला नाम अनुब्रत मंडल का है। बीरभूम के कद्दावर नेता अनुब्रत मंडल ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। वह अब ऋतब्रत बनर्जी के खेमे में शामिल हो गए हैं। ऋतब्रत गुट ने उन्हें बीरभूम का नया जिला अध्यक्ष बनाया है। इस फैसले को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। ऋतब्रत बनर्जी के गुट ने न केवल जिला अध्यक्षों की घोषणा की, बल्कि पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन को अपनी राज्य समिति में शामिल कर लिया है।

आठ माह में दूसरी बार कम पूछे गए सवाल, जवाबदेही पर उठे सवाल

मानसून सत्र से पहले विधायकों की सक्रियता घटी

मध्यप्रदेश विधानसभा के 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र से पहले विधायकों की सक्रियता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने इस बार कुल 1,756 प्रश्न ही विधानसभा सचिवालय में जमा किए हैं। यह पिछले सत्रों की तुलना में काफी कम है। खास बात यह है कि मोहन सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में यह दूसरी बार है, जब विधानसभा सत्र से पहले विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।

वेब वार्ता, भोपाल

विधानसभा में प्रश्नकाल को सरकार की जवाबदेही तय करने का सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता है। जनहित से जुड़े मुद्दों, विकास कार्यों की प्रगति, योजनाओं के क्रियान्वयन, वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक लापरवाही पर सरकार से जवाब मांगने के लिए विधायक प्रश्न पूछते हैं। लेकिन इस बार प्रश्नों की संख्या कम रहने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या जनप्रतिनिधियों की सक्रियता पहले जैसी नहीं रही।

दिसंबर सत्र की तुलना में फिर आई गिरावट

इससे पहले दिसंबर 2025 के शीतकालीन सत्र में भी विधायकों ने अपेक्षाकृत कम 1,497 प्रश्न लगाए थे, जो उस समय मोहन सरकार के कार्यकाल में सबसे कम माने गए थे। अब महज आठ महीने बाद मानसून सत्र के लिए भी प्रश्नों की संख्या सामान्य से कम रहने पर विधानसभा की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा सचिवालय के अनुसार इस बार कुल 1,756 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। इनमें 1,091 प्रश्न ऑनलाइन तथा 665 प्रश्न ऑफलाइन माध्यम से जमा किए गए हैं। तकनीकी सुविधाएं बढ़ने के बावजूद प्रश्नों की संख्या में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो सकी।

प्रश्नकाल से तय होती है सरकार की जवाबदेही

विधानसभा का प्रश्नकाल लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसी दौरान विधायक विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों पर सरकार से जवाब मांगते हैं। सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली, कानून-व्यवस्था, भर्ती, योजनाओं के क्रियान्वयन और भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर पूछे गए प्रश्नों के आधार पर सरकार को सदन में जवाब देना पड़ता है। कई मामलों में प्रश्नों के बाद जांच, कार्रवाई और नीतिगत बदलाव भी देखने को मिले हैं।

विपक्ष के लिए बड़ा अवसर

20 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून सत्र कई मुद्दों पर हंगामेदार रहने की संभावना है। प्रदेश में खराब सडकें, कर्मचारियों के लंबित प्रमोशन, भर्ती प्रक्रियाएं, बिजली व्यवस्था, मानसून से जुड़े इंतजाम, किसानों की समस्याएं, कानून-व्यवस्था तथा विभिन्न विभागों में कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। हालांकि प्रश्नों की संख्या कम रहने से विपक्ष के आक्रामक तेवरों पर भी चर्चा हो रही है। विधानसभा मामलों के जानकारों का मानना है कि प्रश्नों की संख्या केवल आंकड़ा नहीं होती, बल्कि यह विधायकों की सक्रियता का भी संकेत देती है। जितने अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, उतनी ही अधिक सरकार की जवाबदेही तय होती है और प्रशासनिक व्यवस्था पर निगरानी मजबूत होती है।

ओंकारेश्वर का पारदर्शी दान मॉडल बना मिसाल

वेब वार्ता, भोपाल

देशभर में मंदिरों में आने वाले चढ़ावे और उसके प्रबंधन को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की खबरों के बाद एक बार फिर मंदिरों की वित्तीय व्यवस्थाएं चर्चा में हैं। ऐसे में मध्यप्रदेश के ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर की व्यवस्था जानना महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां हर वर्ष करोड़ों रुपए का दान प्राप्त होता है और उसके प्रबंधन के लिए एक निर्धारित ट्रस्ट प्रणाली कार्यरत है।

ओंकारेश्वर मंदिर को वर्ष 1959 में मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के तहत सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित किया गया था। मंदिर के संचालन और वित्तीय प्रबंधन के लिए सात सदस्यीय ट्रस्ट गठित है। इसमें मांधाता के राव मैनेजिंग ट्रस्टी होते हैं, जबकि उनके द्वारा एक अन्य ट्रस्टी नामित किया जाता है। इसके अलावा रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और नगर पंचायत की ओर से भी ट्रस्टी नियुक्त किए जाते हैं।

वर्तमान में राव पुष्पेंद्र सिंह मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। खंडवा कलेक्टर ऋषव गुप्ता ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं, जबकि पुनासा एसडीएम पंकज वर्मा ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अशोक महाजन सहायक मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ट्रस्ट का कहना है कि नियमित ऑडिट, दस्तावेजी रिकॉर्ड और प्रशासनिक निगरानी के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित दान का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप और पारदर्शी तरीके से किया जाए।

पूरा रिकॉर्ड डिजिटल

ट्रस्ट का मुख्य कार्य मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे का व्यवस्थित प्रबंधन करना है। ऑनलाइन प्राप्त होने वाली दान राशि का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है, जबकि ऑफलाइन दान देने वाले श्रद्धालुओं को रसीद उपलब्ध कराई जाती है। आवश्यकता होने पर आयकर अधिनियम के तहत 80 सी प्रमाणपत्र भी जारी किया जाता है।

मंदिर ट्रस्ट का वार्षिक बजट लगभग 15 से 20 करोड़

दानपेटियों से प्राप्त राशि की गिनती प्रशासनिक निगरानी में की जाती है। ट्रस्ट के अनुसार, यह प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और वीडियोग्राफी के साथ संपन्न होती है। गिनती पूरी होने के बाद राशि को विधिवत बैंक खातों में जमा कराया जाता है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता बनी रहे। मंदिर ट्रस्ट का वार्षिक बजट लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए के बीच रहता है। इस राशि का उपयोग मंदिर के रखरखाव, अधोसंरचनात्मक विकास कार्यों, धार्मिक व्यवस्थाओं तथा कर्मचारियों के वेतन और अन्य प्रशासनिक खर्चों पर किया जाता है।

ई-20 पेट्रोल लागू करने में जल्दबाजी? के आरोप पर सरकार ने दिए तर्क

वेब वार्ता, नई दिल्ली

भारत सरकार द्वारा ई-20 पेट्रोल के लॉन्च के बाद से यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि क्या पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण (एथनॉल ब्लेंडिंग) को लागू करने में जल्दबाजी की गई है? आलोचकों का तर्क है कि ब्राजील जैसे देशों ने इस दिशा में दशकों तक शोध और विकास किया, जबकि भारत ने त्वरित गति से इसे अपनाया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इन आशंकाओं को दूर करते हुए आधिकारिक आंकड़ों और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ सिलसिलेवार जवाब प्रस्तुत किया है, जो इस कार्यक्रम की लंबी और सुविचारित यात्रा को दशार्ते हैं। मंत्रालय का कहना है कि भारत ने 2030 तक ई-20 पेट्रोल का लक्ष्य रखा था, जिसे पांच साल पहले, 2025 में ही प्राप्त कर लिया गया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इसमें जल्दबाजी की गई। वास्तव में, एथनॉल कोई नया ईंधन नहीं है; सदियों पहले हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली कारों में एथनॉल का ही प्रयोग किया था। ब्राजील और अमेरिका जैसे कई देशों में तो दशकों से इस वैकल्पिक ईंधन का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। भारत का कार्यक्रम भी एक दशक से अधिक पुराना है।

भारत में एथनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम की जड़ें वर्ष 2001 में शुरू हुए एक पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं। 2005 में इसकी आधिकारिक घोषणा की गई और 2006 में देश के कई राज्यों में 5 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण की शुरूआत भी हो गई। जनवरी 2013 में, एथनॉल नीति का एक सुदृढ़ ढांचा सार्वजनिक किया गया था, जो इस दिशा में सरकार की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

एक व्यापक रणनीति तैयार की

हालांकि, वर्ष 2014 तक केवल 1.5 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य ही हासिल किया जा सका था, जो शुरूआती चुनौतियों की ओर इशारा करता है। वर्तमान में, भारत में एथनॉल उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने पर निर्भर है, और देश में लगभग 400 करोड़ लीटर एथनॉल का उत्पादन हो रहा है। वर्ष 2018 में, सरकार ने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल की शुरूआत की, जिसने एथनॉल उत्पादन और उपयोग के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की। इस नीति के तहत पेट्रोलियम मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन विभाग, रेलवे, तेल कंपनियां और विभिन्न विशेषज्ञ एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो दशार्ता है कि यह एक बहुआयामी और समन्वित प्रयास है। वर्ष 2021 में, नीति आयोग ने एथनॉल ब्लेंडिंग के लिए एक विस्तृत रोडमैप जारी किया, जिसमें ऑटोमोबाइल उद्योग, तेल कंपनियों, कृषि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों को शामिल किया गया। इस व्यापक भागीदारी का उद्देश्य सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर लक्ष्य प्राप्त करना था।

मंदिर दर्शन करने जा रहे भक्तों के सामने अचानक आ गया तेंदुआ, फिर मची भगदड़

तिरूमला। आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुपति बालाजी मंदिर जाने वाले भक्तों के लिए एक बेहद डराने वाली खबर सामने आ रही है. तिरुमला के प्रसिद्ध अलीपिरी पैदल मार्ग पर अचानक एक खूंखार तेंदुआ आ धमका. तेंदुए को देखते ही वहां मौजूद श्रद्धालुओं के होश उड़ गए और चारों तरफ चीख-पुकार मच गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. इस घटना के बाद से मंदिर जाने वाले भक्तों में भारी दहशत का माहौल है.

वियतनाम में बड़ा हादसा

भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही नाव पलटी, 15 की मौत

वेब वार्ता, वियतनाम । हनोई में भारतीय दूतावास ने जानकारी दी कि शनिवार को वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास कई भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही एक स्पीडबोट (नाव) पलट गई. यहां पर खोज और बचाव अभियान जारी है. भारतीय मिशन ने सूचना देने के लिए कंट्रोल रूम बनाए हैं. दूतावास ने कहा कि स्थानीय अधिकारी घटना की पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हादसे में 15 लोगों की मौत हो चुकी है.

वियतनाम में भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया, आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वियतनाम में फु

क्वोक द्वीप के पास कुछ घंटे पहले पलटी नाव में ये 32 भारतीय पर्यटक सवार थे.

ब्रह्मपुत्र नदी पर हाइड्रोपावर डैम से बढ़ जाएगा भूकंप, लैंडस्लाइड का खतरा

वेब वार्ता, नई दिल्ली। चीन तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोपावर डैम का निर्माण कर रहा है, जिस पर भारत भी नजर रख रहा है। अब इस प्रोजेक्ट के खिलाफ चीन के अंदर से भी आवाजें उठाने लगी है। यह प्रोजेक्ट भारत के अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर से केवल 50 किलोमीटर दूर है। तिब्बत की त्सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। शी जिनपिंग के साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है कि इस डैम के बनने से भूकंप, लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाएगा।

चीनी सरकार के मुताबिक यार्लुंग त्सांगपो नदी के निचले हिस्से पर हाइड्रोपावर डैम कम कार्बन-उत्सर्जन वाला विकास बढ़ाने की ग्रीन प्रोजेक्ट है। इसमें कहा गया है कि नदी के प्रचुर जल ऊर्जा संसाधन से आसपास के इलाके में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का विकास बढ़ाया जाएगा और स्वच्छ ऊर्जा के आधार का निर्माण किया जाएगा। परियोजना का निर्माण पूरा होने के बाद बिजली, जल संरक्षण और परिवहन का स्तर बेहतर होने की बात

कही गई है।

भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की गतिविधियों को लेकर कई बार चिंता व्यक्त की है। इससे जल सुरक्षा, मौसम पर असर और निचले इलाकों में रहने लोगों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। पिछले महीने चीन की सरकारी स्वामित्व वाली चाइना जियोलॉजिकल सर्वे में बताया गया कि पाइझेन फॉल्ट की एक भूकंपीय दरार ठीक उसी जगह से गुजरती है जहां इस हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है।

शोधकताओं ने कहा कि पाइझेन फॉल्ट बांधों, सड़कों, पुलों और सुरंगों समेत आसपास के स्ट्रक्चर की स्थिरता पर बड़ा प्रभाव डालेगा। यहां जमीन के नीचे दरार की वजह से आस-पास की चट्टानें टूट चुकी हैं और बहुत कमजोर हो चुकी है। कमजोर चट्टान के कारण बांध का पिलर वजन संभाल नहीं सकता और उसकी मजबूती खतरे में पड़ सकती है। इस वजह से किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के टूटने या ढहने का जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।

चीनी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बांध के जलाशय के आसपास की जमीन की बनावट बहुत ढीली है और वहां की मिट्टी-पत्थर मजबूती से जुड़े नहीं हैं। इस वजह से वहां बड़े पैमाने पर पहाड़ खिसकने या भारी भूस्खलन होने की आशंका बढ़ गई है। उन्होंने 2017 में तिब्बत के मिलिन में आए 6.9 तीव्रता के भूकंप का भी हवाला दिया, जो इस बात का प्रमाण है कि यह फॉल्ट अभी भी एक वास्तविक भूकंपीय खतरा बना हुआ है।

बारातियों से भरी तेज रफ्तार पिकअप पलटने से 2 की मौत, 14 घायल, 4 की हालत गंभीर

छतरपुर, वेब वार्ता

मध्य प्रदेश के छतरपुरजिले के नौगांव थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बारातियों से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 बाराती घायल हो गए। इनमें दूल्हे के पिता सहित चार लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

पुलिस के अनुसार, बारात टीकमगढ़ जिले के ग्राम बिदारी से उत्तर प्रदेश के अतर्रा जा रही थी। पिकअप वाहन यूपी 94 एटी 3394 में करीब 20 बाराती सवार थे। जैसे ही वाहन नौगांव स्थित पीएम श्री कॉलेज के पास पहुंचा, चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और पिकअप सड़क पर पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पिकअप तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। बताया जा रहा है कि चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे वाहन असंतुलित होकर सड़क की दूसरी ओर पलट गया। चालक के शराब के नशे में होने की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस इस पहलू की जांच कर रही है।

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही नौगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शुरूआती जांच में तेज रफ्तार और चालक के नशे में होने की आशंका पर भी जांच की जा रही है।

दो की मौके पर मौत, चार गंभीर

हादसे में किशोरी अहिरवार (48) और नितिन अहिरवार (17) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूल्हे के पिता नंदलाल अहिरवार, संतोष, चेचे और भजनलाल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को पहले नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चार घायलों को जिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

संपादकीय

परमाणु बम बनाएगा ईरान!

युद्ध का तनाव इतना बढ़ चुका है कि ईरान परमाणु बम बनाने की सोचने लगा है। वह परमाणु अप्रसार सन्धि (एनपीटी) से भी बाहर आ सकता है। फिलहाल ऐसी संभावनाएं और आशंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ इन्हें ही परमाणु बम बनाने का आधार मान रहे हैं। रूस ने भी कई बार बयान दिया है कि हालात ईरान को एटम बम बनाने को बाध्य कर रहे हैं। इस संदर्भ में रक्षा विशेषज्ञ ईरान की तुलना उत्तर कोरिया से कर रहे हैं। उत्तर कोरिया 1985 में एनपीटी का सदस्य था। फिर भी उसने रहस्यमयी परमाणु परीक्षण किए और छोटे-छोटे बम भी बना लिए। उसने 2003 में एनपीटी को छोड़ दिया। आज वह सरेआम विनाशक मिसाइलों के परीक्षण कर रहा है। उसके पास कितने परमाणु बम हैं, उसका सत्यापित हिसाब किसी के पास भी नहीं है, लेकिन अमरीका और यूरोपीय देश उससे आशंकित रहते हैं। क्या ईरान युद्ध ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है कि ईरान उत्तर कोरिया बन सकता है? वैसे ईरान के पास करीब 440 किग्रा. संवर्धित यूरेनियम बताया जाता है। यह संवर्धन 60 फीसदी से अधिक है, जिससे छोटे एटम बम बनाए जा सकते हैं! जब तक अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ईरान के परमाणु कार्यक्रम का निरीक्षण कर रही थी, उसके आधार पर अब भी आकलन किए जा रहे हैं कि ईरान ने परमाणु बम नहीं बनाया है। दिवंगत सुप्रीम लीडर खामेनेई भी घोषित रूप से परमाणु बम बनाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की इस बाबत सोच अभी तक अस्पष्ट है। ईरान के सबसे बड़े और प्रमुख परमाणु केंद्र नतांज सहित फोर्डो और इस्फहान परमाणु केंद्रों में यूरेनियम संवर्धन अब भी जारी है, ऐसी खबरें आती रही हैं। ये जमीन के बहुत नीचे और सुरक्षित परमाणु केंद्र हैं, जिन्हें अमरीका और इजरायल अभी तक नष्ट करने में नाकाम रहे हैं। अमरीकी सेना ने जिस बुशहर परमाणु प्लांट के निकट अभी हवाई हमले, बम विस्फोट किए हैं, वह ईरान का एकमात्र सक्रिय परमाणु बिजलीघर है। इस 1000 मेगावाट के संयंत्र को जर्मनी ने बनाना शुरू किया था, लेकिन वह अधूरा छोड़ कर भाग गया। फिर रूस ने इसे अंतिम रूप दिया। यह ईरान का सर्वाधिक संवेदनशील परमाणु प्लांट है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने बिजली संयंत्रों और महत्वपूर्ण पुलों पर हमले करने का ऐलान किया है। बीते गुरुवार को अमरीकी हमले में उन रेल पुलों को तबाह किया गया है, जो तेहरान और मशहद को जोड़ते हैं। मशहद में ही खामेनेई को सुपुर्द-ए-खाक किया गया है। अमरीकी हमलों में पहली बार चाबहार बंदरगाह के ट्रैफिक कंट्रोल टॉवर और आईआरजीसी के इमाम अली बेस को निशाना बनाया गया है। जाहिर है कि नुकसान भी हुआ है। इस बंदरगाह को विकसित करने में भारत ने भी 1400 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है, लिहाजा हमारा भी नुकसान हुआ है। बहरहाल बीते दिनों एक खबर आई थी कि बुशहर में ही करीब 2100 किग्रा. प्लूटोनियम का भंडार है। बेशक इससे 200 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। यह खबर फोर्ब्स के अलावा रॉयटर्स और गूगल ने भी जारी की थी। व्याख्या की गई कि ईरान यथाशीघ्र परमाणु शक्ति बनना चाहता है। अस्तित्व बचाने का यही आखिरी विकल्प उसे लगता है। इसे ईरान आत्मरक्षा का कवच करार देता है, लिहाजा उसने परमाणु केंद्रों और ठिकानों पर सैन्य तैनाती करना भी शुरू कर दिया है। नतांज केंद्र के तहत यूरेनियम जमीन के 300 फुट नीचे दबा है। जो सर्वधित किया जा रहा है, उसे अन्यत्र शिफ्ट किया जा रहा है। यह खुलासा सेटेलाइट तस्वीरों से भी हुआ है। ईरान का दावा है कि प्लूटोनियम से भी खतरनाक, विनाशक हथियार बनाए जा सकते हैं। रिएक्टर ग्रेड प्लूटोनियम से भी एटम बम बनाया जा सकता है। इस तरह संवर्धित यूरेनियम और प्लूटोनियम को मिला कर ईरान के पास करीब 2550 किग्रा. विस्फोटक सामग्री है। इस मात्रा से वह व्यापक नरसंहार कर सकता है और परमाणु बम के विकिरण से कितनी पीढ़ियां विकलांग होंगी, इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। क्या संयुक्त राष्ट्र और आईएईए ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक सकते हैं? अब युद्ध का फोकस परमाणु कार्यक्रम ही है। होर्मुज तो आंशिक तौर पर आज भी खुला है और 10-12 जहाज-टैंकर ईरान ने गुजरने दिए हैं। टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक, ईरान के सुपर टैंकर के जरिए करीब 1 करोड़ बैरल तेल सप्लाई किया गया है। इस तेल की कीमत 7500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ज्यादातर तेल चीन रवाना किया गया है। देर-सबेर होर्मुज का मुद्दा बिल्कुल सुलझना ही है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम-प्लूटोनियम का मुद्दा इतना पेचीदा हो गया है कि ईरान मानने को राजी नहीं है। अमरीका ही नहीं, इजरायल भी अड़े हैं कि किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। तो अमरीका-ईरान में कभी भी समझौता किन शर्तों पर होगा, यह बिल्कुल अनिश्चित है? बहरहाल, विश्व को शांति की जरूरत है।

मोदी को मिले पुरस्कारों पर गार्जियन की हताशा

दि गार्जियन अखबार ने मोदी और भारत की छवि धूमिल करने के लिए अंग्रेजी में एक लेख लिखा, जिसका सारांश यह है कि कोई झूठे भी पुरस्कार देने के लिए बुलाए तो प्रधानमंत्री मोदी दौड़े दौड़े चले जाते हैं। मतलब यह अखबार कहना चाह रहा है कि मोदी पुरस्कार के भूखे हैं, साथ ही यह भी जताने की कोशिश कर रहा है, जिन देशों ने मोदी को उनकी विदेश यात्रा के दौरान पुरस्कार दिए, उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को इन देशों ने फिजूल में पुरस्कार दिए हैं।

गार्जियन ने यह लेख लिख कर मोदी सहित भारत का तो अपमान किया ही है, साथ ही मोदी को पुरस्कार देने वाले उन देशों के नागरिकों, पुरस्कारों और उन देशों के राष्ट्रप्रमुखों का भी अपमान किया है। इस लेख की भड़ास के बावजूद पीएम मोदी को पुरस्कारों का सिलसिला थम नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान ह्वबिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशियाह्ल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रदान किया। वर्ष 2016 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमरीका के देशों से ऐसे 34 सम्मान मिल चुके हैं। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को मिले सम्मानों में सबसे अधिक हैं। इनमें से कुछ सम्मान सदियों पुराने हैं, जबकि कुछ सम्मान संबंधित देशों की सम्मान प्रणाली में हाल ही में शामिल किए गए हैं। गार्जियन का यह लेख भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का कुत्सित प्रयास है।

विश्व का बड़ा और प्रभावशाली शायद ही कोई देश बचा होगा, जिसके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने मोदी और भारत की तारीफ नहीं की होगी। दरअसल यह तारीफ पाश्चात्य मीडिया पचा नहीं पा रहा है। पचा इसलिए भी नहीं पा रहा है कि भारत न सिर्फ घरेलू स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तरक्की के झंडे गाड़ रहा है। चंद्रयान और मंगलयान मिशन की कामयाबी इसके बड़े उदाहरण हैं, जो विकसित देश भी हासिल नहीं कर सके। यह अखबार यह भी भूल गया कि जब कोरोना काल में पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, तब भारत ने ही कोरोना वैक्सीन दर्जनों देशों को निशुल्क भेज कर करोड़ों लोगों की जानें बचाने का काम किया था। क्या ऐसे परोपकारी कार्यों के लिए उन्हें विदेशी पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। गार्जियन ने इसका जिक्र कभी नहीं किया कि विश्व को मोदी नेतृत्व में भारत ने क्या-क्या दिया है। भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसी सस्ती और सुलभ डिजिटल पेमेंट प्रणाली को नेपाल, भूटान, सिंगापुर, यूएई और मॉरीशस ने अपना लिया है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो भारत की प्राचीन धरोहर योग को मोदी सरकार के प्रयासों से वैश्विक मान्यता मिली। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोदी सरकार के प्रयासों से ही अफ्रीकी संघ को जी-20 का स्थायी सदस्य बनाया गया। भारत प्राकृतिक आपदा के दौरान विश्व के देशों के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ा रहा है। तुर्किये और सीरिया में आए भूकंप के दौरान मिशन सागर और ऑपरेशन दोस्त के जरिए विश्व स्तर पर मानवीय सहायता पहुंचाई गई। वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप के बाद ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत बचाव दल और पोर्टेबल अस्पताल भेजे गए। म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा (2025) और ऑपरेशन सहायता (2008) के तहत भूकंप व चक्रवात के दौरान भारी राहत सामग्री व चिकित्सा सुविधाएं दी गईं। श्रीलंका में सुनामी (2004) में ऑपरेशन रेनबो और चक्रवात (2025) में ऑपरेशन सागर बंधु के माध्यम से सहायता प्रदान की गई। भारतीय नौसेना ने हालिया समुद्री सुरक्षा अभियानों (मुख्य रूप से अरब सागर और अदन की खाड़ी) में 520 से अधिक लोगों की जान बचाई है और ईरान, लाइबेरिया, माल्टा और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइन्स जैसे विभिन्न देशों के झंडे वाले जहाजों को समुद्री लुटेरों से सुरक्षित मुक्त कराया है।

इन अभियानों की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि नौसेना ने बिना किसी राष्ट्रीय भेदभाव के, पाकिस्तानी और ईरानी नागरिकों सहित कई देशों के नाविकों को भी बचाया है। गार्जियन खासकर विदेशी मीडिया को कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन पर भारी परेशानी है। भारत में उन्हें यह उल्लंघन नजर आता है। अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राज किया। अंग्रेज शासकों ने इस अवधि में भारतीयों पर अत्याचारों के सारे रिकार्ड तोड़ दिए। अंग्रेज व्यापारी बन कर आए और तानाशाह बन बैठे, खूब लूट खसूट की और भारत से सारा मालमत्ता समेट कर चंपत हो गए। आज भी कोहिनूर का हीरा इन्हीं अंग्रेजों के पास है, जो यह बताता है कि किस तरह इन्होंने भारत में लूटपाट मचाई थी। ऐसे मानवाधिकारों के उल्लंघन गार्जियन जैसे अखबारों को दिखाई नहीं देते। मानवाधिकारों के इन विदेशी पैरोकारों को जलियांवाला बाग दिखाई नहीं देता, जहां निहत्थे प्रदर्शकारियों को चारों तरफ से घेर कर एक अंग्रेज अधिकारी डायर ने गोलियों से भून डाला था। गार्जियन को यह कभी दिखाई नहीं दिया कि किस तरह केंद्र सरकार ने मुसलमानों की भलाई का एक ऐतिहासिक काम किया, जिसे करने से पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री डरते रहे। देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद मिलने वाला कानूनी हक दिलवाया है, जिन्हें पहले पति तीन बार तलाक तलाक बोल कर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। कांग्रेस ने मुसलमानों के वोट के डर से सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो के फैसले को ही पलट दिया था, जिसमें कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ तत्कालीन कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कानून बना दिया था। विदेशी अखबारों को तकलीफ हो रही है कि मोदी राज में कैसे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जब भारत ने ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया तब खीझ उतारने के लिए कह दिया कि मोदी पुरस्कार के लिए दौड़े चले आते हैं।

जिला स्तर, वार्ड स्तर, राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी और निजी क्षेत्र में पुरस्कार के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इन्हें पाने के लिए लोग अपनी पूरी उम्र खपा देते हैं। उसमें भी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती है, तब कहीं जाकर किसी एक का चयन किया जाता है। ऐसे में देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले पुरस्कार का मापदंड कितना कठोर होगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। इन पुरस्कारों में पुरस्कार देने वाली सरकार के साथ उन देशों के करोड़ों लोगों की भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। चलो मान भी लिया जाए कि किसी एक देश ने भारत से कुछ फायदा लेने के लिए कोई पुरस्कार दे दिया होगा, पर मोदी को तो दर्जनों देशों के सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं, तो क्या इन सब देशों को मोदी सरकार फायदा पहुंचाएगी, वो भी सिर्फ एक पुरस्कार के कारण, यदि ऐसा हुआ होता तो अब तक देश में तूफान आ जाता, कांग्रेस और विपक्षी दलों ने आसमान सिर पर उठा लिया होता। गार्जियन का यह लेख सिर्फ हताशा ही प्रकट करता है। इससे पहले भी इसी तरह के विदेशी अखबारों में लेखों के जरिए भारत की छवि और विकास की तरफ बढ़ते कदमों को रोकने का असफल प्रयास किया जाता रहा है।

योगेंद्र योगी
स्वतंत्र लेखक

प्रसन्न मन, स्वस्थ जीवन: मुस्कान में छिपी सफलता और सुख का महामंत्र

कुदरत द्वारा रचित इस अनमोल खूबसूरत सृष्टि में रचनाकर्ता ने मानवीय जीवन में अनेक गुण दोषों को शामिल कर संजोया है, इसका उपयोग करने सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमता का भी सृजन कर दिया है।बस! जरूरत है अब माननीय जीव को उसे गुण-दोष सुख-दुख खुशियां-गम प्रसन्नता-दुख इत्यादि का चुनाव कर अपने जीवन को सफल और असफल बनाएं उसके ऊपर है,क्योंकि मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र मानता हूं कि, प्रसन्नता और सुख दुख भी बौद्धिक क्षमता के आधार पर माननीय जीव को खुद चुनना होता है! इसलिए आज हम मन की प्रसन्नता पर उसके गुणों, प्रक्रिया सुजन करने के तरीकों पर इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे।

साथियों बात अगर हम प्रसन्नता की करें तो खुलकर हंसना, मुस्कुराना, प्रसन्न रहना, मन की प्रसन्नता खुद सृजित की हुई दवा के समान है, क्योंकि इसमें सब दुख तो नष्ट होते हैं,जीव अपने कर्म में असफल नहीं होता। बुद्धि तुरंत स्थिर रहती है। सामाजिक प्रतिष्ठा और गुणों की सुगंध दूर तक जाती है एक अलग हस्मुख व्यक्तित्व की हमारी छाया हमारे अपने परिचितों सहयोगियों पर पड़ती है। प्रसन्नता हमारा ऐसा अनमोल खजाना है, जिसे जितना लूटाएंगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा! खिलखिलाते चेहरे और प्रसन्नता की आंखों की चमक मनीषियों को दुर्लभ पूंजी है, क्योंकि प्रसन्नता सुकून से जीने की कुंजी है। यह खजाना तब बढ़ता है जब हम दूसरों की खुशीयों में अपनी खुशी को समाहित करते हैं। हमें छोटी-छोटी चीजों में प्रसन्नता, सुख ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, विश्वसनीय मन के भाव की खुशी का भाव अभूतपूर्व सफलता और दूरगामी सकारात्मक परिणाम होता है। आध्यात्मिकता, उदारता, परोपकार, सहनशीलता, सहिष्णुता इत्यादि मन की प्रसन्नता के प्रमुख स्त्रोतों में से कुछ हैं, जिनको जीवन में अपनाने की जरूरत को रेखांकित किया जा सकता है।

साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता इंडेक्स रिपोर्ट इत्यादि अन्तर्राष्ट्रीय स्तरपर प्रसन्नता के मूल्यों की करें तो प्रसन्नता को हाई वैश्विक टॉनिक माना जाता है।प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है अलग-अलग देशों के प्रसन्नता से रहने के क्रमांक बताए जाते हैं, परंतु बहुत हैरानी की बात है प्रसन्नता इंडेक्स में अनेक पूर्ण विकसित देशों के साथ ही भारत भी पिछड़ा हुआ है जो रेखांकित करने वाली बात है! विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में 146 देशों की रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड लगातार 5 वर्षों से प्रथम और डेनमार्क द्वितीय और आयरलैंड तृतीय स्थान पर है।जबकि इस रिपोर्ट में भारत 136 वी रैंक पर है याने लास्ट टॉप टेन इतनी खराब हालात जो आश्चर्य वाली बात है।

साथियों बात अगर हम मन की प्रसन्नता के गुण एवं लाभों की करें तो, प्रसन्नता तो व्यक्ति का मानसिक गुण है, जिसे व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन के अभ्यास में लाना होता है। प्रसन्नता व्यक्ति के अंतर्मन में छिपे उदासी, तृष्णा और कुंठाजनित मनोविकारों को सदा के लिए समाप्त कर देती है। वस्तुत: प्रसन्नता चुंबकीय शक्ति संपन्न एक विशिष्ट गुण है। प्रसन्नता दैवी वरदान तो है ही, यह व्यक्ति के जीवन की साधना भी है। व्यक्ति प्रसन्न रहने के लिए एक खिलाड़ी की भांति अपनी जीवन-शैली और दृष्टिकोण को अपना लेता है। उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता-असफलता, जय-पराजय, और सुख-दुख उसके चिंतन का विषय नहीं होता। वह तो अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है।प्रसन्नता मानवों में पाई जाने वाली भावनाओं में सबसे सकारात्मक भावना है। इसके होने के विभिन्न कारण हो सकते हैं: अपनी इच्छाओं की पूर्ति से संतुष्ट होना। अपने दिन-रात के जीवन की गतिविधियों को अपनी इच्छाओं के अनुकूल पाना। किसी अचानक लाभ से लाभांवित होना। किसी जटिल समस्या का समाधान प्राप्त होना। साथियों बात अगर हम प्रसन्नता के लक्ष्यों की प्राप्ति की करें तो, प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेता है। यदि वह असफल भी हो जाता है तो निराश होने और अपनी विफलता के लिए दूसरों को दोष देने की अपेक्षा अपनी चूक के लिए आत्मनिरीक्षण करना ही उचित समझता है।ज्ञानीजन और अनुभवी बताते हैं कि प्रसन्नता जैसे दैवीय-वरदान से कुतर्की और षड्यंत्रकारी लोग सदैव वंचित रह जाते हैं। प्रसन्न व्यक्ति स्वयं को प्रसन्न रखकर दूसरों को भी प्रसन्न रखने की अद्भुत सामर्थ्य रखता है। प्रसन्नता को प्रभु-प्रदत्त संपदा समझने वाले व्यक्ति ही सदैव सुखी रहते हुए यशस्वी, मनस्वी, महान और पराक्रमी बनकर समाज और राष्ट्र के लिए आदर्श स्थापित करने में सक्षम हो सकते हैं। प्रसन्नता ही सुखी जीवन का मूल मंत्र है। प्रसन्नता हमारा अनमोल खजाना है। प्रसन्नता को जरूर लुटाइए फि र देखिए, उसका खजाना बढ़ता चला जाएगा ।भलाई करना कर्त्तव्य नहीं, आनन्द है । क्योंकि वह प्रसन्नता को पोषित करता है । सबको प्रसन्न करने की शक्ति सब में नहीं होती । प्रसन्नता आत्मा को शक्ति प्रदान करती है । प्रसन्नतापूर्वक उठाया गया बोझ हल्का महसूस होता है। प्रसन्नता शब्द का प्रयोग मानसिक या भावनात्मक अवस्थाओं के संदर्भ में किया जाता है, जिसमें संतोष से लेकर तीव्र आनंद तक की सकारात्मक या सुखद भावनाएं शामिल हैं।इसका उपयोग जीवन संतुष्टि, व्यक्तिपरक कल्याण, यूडिमोनिया, उत्कर्ष और कल्याण के संदर्भ में भी किया जाता है इसलिए हर व्यक्ति ने इस गुण को अपने में समाहित कर जीवन को सफल बनाने के मंत्र को अपनाना चाहिए। अत: अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि खिलखिलाती मुस्कान की शक्ति: मन की प्रसन्नता से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक समृद्धि मन की प्रसन्नता ही सबसे बड़ी संपत्ति: मुस्कान से महके जीवन, परिवार और समाज प्रसन्न मन, स्वस्थ जीवन: मुस्कान में छिपी सफलता और सुख का महामंत्र

लेखक - एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं
(संकलनकर्ता लेखक - कर विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यम सीए (एटीसी) (यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

बढ़ती आबादी और सतत विकास की चुनौती

विश्व जनसंख्या दिवस हमें यह भी संदेश देता है कि विकास तभी सार्थक होगा जब वह समावेशी और टिकाऊ हो। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा, रोजगार सृजन, महिलाओं की भागीदारी और सामाजिक समानता जैसे पहलुओं पर समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है। सरकार, सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों और नागरिकों को मिलकर जनसंख्या संबंधी चुनौतियों का समाधान खोजना होगा। अंतत:, विश्व जनसंख्या दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प लेने का अवसर है।

हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या से जुड़े मुद्दों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना तथा परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, शिक्षा और सतत विकास के महत्व को रेखांकित करना है। इस दिवस की शुरूआत 1989 में यूएन द्वारा की गई थी। इसकी प्रेरणा 11 जुलाई 1987 को मिली, जब विश्व की जनसंख्या लगभग 5 अरब तक पहुंच गई थी। यह दिन केवल जनसंख्या पर चर्चा करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन का अधिकार है। आज विश्व की जनसंख्या 8 अरब से अधिक हो चुकी है। जनसंख्या वृद्धि ने विकास के अनेक अवसर दिए हैं लेकिन इसके साथ संसाधनों पर दबाव, पर्यावरणीय संकट, बेरोजगारी, गरीबी, जल संकट, खाद्य सुरक्षा और शहरीकरण जैसी चुनौतियां भी बढ़ी हैं।

यदि जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों के बीच संतुलन नहीं बनाया गया तो आने वाले वर्षों में इन समस्याओं की गंभीरता और बढ़ सकती है। भारत विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल है। विशाल जनसंख्या भारत की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। यदि देश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार उपलब्ध कराया जाए, तो यही जनसंख्या आर्थिक विकास का आधार बन सकती है। दूसरी ओर यदि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर पर्याप्त न हों, तो सामाजिक और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। जनसंख्या वृद्धि का सबसे अधिक प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ता है। बढ़ती आबादी के कारण जल, भूमि, वन और ऊर्जा संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। शहरों का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे प्रदूषण, यातायात, कचरा प्रबंधन और आवास जैसी समस्याएं भी गंभीर होती जा रही हैं। जलवायु परिवर्तन के दौर में संतुलित जनसंख्या वृद्धि और टिकाऊ विकास की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। विश्व जनसंख्या दिवस परिवार नियोजन के महत्व पर भी विशेष बल देता है। छोटे परिवार से माता और बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने से जनसंख्या स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। यही कारण है कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को सतत विकास की आधारशिला माना जाता है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण और जनजागरूकता से जुड़े अनेक कार्यक्रम चला रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य केवल जनसंख्या नियंत्रण नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, किशोर-किशोरियों को सही जानकारी और महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। आज आवश्यकता केवल जनसंख्या बढ़ने या घटने पर चर्चा करने की नहीं, बल्कि मानव संसाधन के समुचित विकास की है। यदि प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण मिले, तो वह देश के विकास में प्रभावी योगदान दे सकता है। इसलिए जनसंख्या नीति का केंद्र मानव विकास होना चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस हमें यह भी संदेश देता है कि विकास तभी सार्थक होगा जब वह समावेशी और टिकाऊ हो। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा, रोजगार सृजन, महिलाओं की भागीदारी और सामाजिक समानता जैसे पहलुओं पर समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है। सरकार, सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों और नागरिकों को मिलकर जनसंख्या संबंधी चुनौतियों का समाधान खोजना होगा।

अंतत:, विश्व जनसंख्या दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प लेने का अवसर है। संतुलित जनसंख्या, स्वस्थ समाज, शिक्षित युवा, सशक्त महिलाएं और सुरक्षित पर्यावरण ही विकसित भारत की मजबूत नींव बन सकते हैं। आइए, 11 जुलाई के अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि जनसंख्या के साथ-साथ मानव विकास, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को भी समान महत्व देंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, समृद्ध और संतुलित भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। देश की बढ़ती जनसंख्या राष्ट्रीय चिंता है। इस पर जन-जागरूकता जरूरी है। शिक्षित और जागरूक परिवार जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में हैं। समृद्ध परिवारों की प्रजनन दर गरीब परिवारों की प्रजनन दर से कम है। जनसंख्या में कमी, बेहतर पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे सभी लक्ष्यों को पाने के लिए सरकारों और सामाजिक संस्थाओं के बीच बेहतरीन सामंजस्य की जरूरत है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना तथा अधिक बच्चों को जन्म देने के दृष्टिकोण और सोच को बदलना आदि कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। हमें छोटे परिवार का महत्व समझना होगा। अगर परिवार छोटा होगा, तो जरूरी सुविधाएं जुटाना आसान हो जाता है।

प्रो. मनोज डोगरा
शिक्षाविद

आलेख

दो टूक - मानसून की चुनौती: आखिर स्मार्ट शहर भी क्यों

मानसून ने इस वर्ष अपने आगमन के साथ ही देश के बड़े हिस्से में राहत से अधिक आफत का संदेश दिया है। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश तक प्रकृति का रौद्र रूप साफ दिखाई दे रहा है।

भारी बारिश, भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारा बुनियादी ढांचा और प्रशासनिक तैयारी अभी भी इस प्राकृतिक चुनौती का सामना करने में सक्षम नहीं है। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग-244 कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसी घटनाएं न केवल आवागमन को बाधित करती हैं बल्कि यह भी दिखाती हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और रखरखाव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में भूस्खलन की घटना में लोगों की मौत और कई लोगों का रेस्क्यू इस बात का संकेत है कि हम जोखिमों को पहले से भांपने में असफल रहे हैं। महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में भी स्थिति भयावह है। उल्हास नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है, जिससे वांगणी के पास स्थित कुडसावरे पुल पूरी तरह जलमग्न हो गया और कई गांवों का संपर्क टूट गया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हर वर्ष की तरह इस बार भी बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है लेकिन इस बार स्थिति और भी गंभीर रही है। महज दो दिनों की बारिश में ही सड़कें नदियों में तब्दील हो गई, पेड़ उखड़ गए, पुराने ढ़ांचे ढह गए और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।

ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हर साल आने वाली इस स्थिति को हम केवल ह्वप्राकृतिक आपदाह्ल कहकर टाल सकते हैं? सच्चाई यह है कि यह केवल प्रकृति का प्रकोप नहीं बल्कि हमारी प्रशासनिक लापरवाही, अनियोजित शहरीकरण और तकनीकी अक्षमता का भी परिणाम है। यदि बारिश से पहले नालों की सफाई, जल निकासी की समुचित व्यवस्था और जोखिम वाले क्षेत्रों का वैज्ञानिक मूल्यांकन समय पर किया जाए तो इन घटनाओं की गंभीरता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मुंबई, पुणे या अन्य महानगरों में जलभराव की समस्या अब अस्थायी नहीं रही बल्कि स्थायी संकट बन चुकी है। इसका मूल कारण है शहरों का अनियोजित विस्तार और प्राकृतिक जल निकासी मार्गों का अतिक्रमण। जहां कभी पानी के बहाव के प्राकृतिक रास्ते थे, वहां आज कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं। नतीजतन, थोड़ी सी बारिश भी शहरों को जलमग्न कर देती है। यह स्थिति केवल मुंबई तक सीमित नहीं है बल्कि अब देश के अधिकांश शहरों में यही तस्वीर देखने को मिलती है। इस बार मानसून ने रेलवे और सड़क परिवहन को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। मुंबई-पुणे रेल मार्ग पर चट्टानी मलबा गिरने से रेल सेवाएं बाधित हो गई। गुजरात के अमरेली में राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा बह जाना इस बात का संकेत है कि हमारी निर्माण प्रणाली प्राकृतिक आपदाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है। यह केवल एक तकनीकी विफलता नहीं बल्कि दीर्घकालिक योजना के अभाव का परिणाम है।

यदि हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो विकसित देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में ह्वलिडारह्ल तकनीक से पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी की जाती है और ह्वरॉकफॉल बैरियर्सह्ल के माध्यम से भूस्खलन को रोका जाता है। रेल और सड़क नेटवर्क में सेंसर आधारित प्रणाली खतरे का पूवार्नुमान लगाकर सेवाओं को नियंत्रित करती है। इसके विपरीत, भारत में आज भी अधिकतर व्यवस्थाएं प्रतिक्रियात्मक हैं अर्थात हादसे के बाद ही कार्रवाई होती है। विश्व बैंक के अनुमानों के अनुसार, भारत को हर वर्ष बारिश से जुड़ी आपदाओं के कारण लगभग 80,000 करोड़ से 1,20,000 करोड़ रुपये तक का आर्थिक नुकसान होता है। यह आंकड़ा केवल आर्थिक क्षति का है जबकि मानवीय जीवन की हानि का मूल्यांकन करना संभव ही नहीं है। हर वर्ष सैंकड़ों लोग केवल इसलिए अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि हम समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठा पाते।

यह स्थिति हमें एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन (ह्वआपदा के बाद राहतह्ल से ह्वआपदा से पहले तैयारीह्ल की ओर) की ओर संकेत करती है। इसके लिए सबसे पहले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ह्वडिजिटल ड्रेनेज ऑडिटह्ल को अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पानी का प्राकृतिक प्रवाह कहां और कैसे होता है। इसके साथ ही ह्वस्पंज सिटीह्ल मॉडल को अपनाना आवश्यक है, जिसमें शहरों को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वे वर्षा के पानी को अवशोषित कर सकें। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए भूवैज्ञानिकों की सलाह को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। ढ़लानों की मजबूती, जल निकासी के उचित चैनल और वनस्पति संरक्षण जैसे उपाय भूस्खलन की घटनाओं को कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, रियल-टाइम वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम और अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करना भी बेहद आवश्यक है। प्रशासनिक स्तर पर भी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी।

हर वर्ष मानसून से पहले नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था के लिए बजट आवंटित किया जाता है लेकिन इसका प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता। यह केवल कागजी कार्रवाई बनकर रह जाता है। जब तक इस पर सख्ती से निगरानी और पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी, तब तक स्थिति में सुधार की उम्मीद करना व्यर्थ होगा। यहां नागरिकों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अतिक्रमण, कचरा प्रबंधन में लापरवाही और पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी भी इस संकट को बढ़ाती है। यदि नागरिक स्तर पर जागरूकता और जिम्मेदारी का भाव विकसित किया जाए तो इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। कुल मिलाकर, हमें यह स्वीकार करना होगा कि प्रकृति को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है लेकिन उसके प्रभाव को कम करना निश्चित रूप से हमारे हाथ में है। इसके लिए आवश्यक है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तकनीकी नवाचार और प्रशासनिक ईमानदारी को एक साथ लेकर चलें। यदि अब भी हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो मानसून हमारे लिए हर वर्ष राहत के बजाय आफत बनकर आता रहेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार, प्रशासन और समाज मिलकर एक दीर्घकालिक और ठोस रणनीति तैयार करें, तभी हम इस प्राकृतिक चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और संतुलित पर्यावरण दे सकते हैं।

लेखक - योगेश कुमार गोयल
(लेखक 36 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार, पर्यावरण विषयों के जानकार तथा पर्यावरण संरक्षण पर चर्चित पुस्तक ह्वप्रदूषण मुक्त सांसेंह्ल के लेखक हैं)
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संक्षिप्त वार्ता

60 लाख की धोखाधड़ी के मामले में घोषित अपराधी को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 11 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली पुलिस ने 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को जानकारी दी कि आरोपी सजा से बचने के लिए कानूनी कार्यवाही से भाग रहा था।

अधिकारियों ने बताया कि सेंट्रल दिल्ली में घोषित अपराधियों और शहर-बदर लोगों के खिलाफ एक विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान, आईपी एस्टेट पुलिस थाने की टीम ने मुकेश कुमार नाम के एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, आरोपी के बारे में शुक्रवार को एक सूचना मिली थी कि वह आईजीआई के डोमेस्टिक टर्मिनल में मौजूद है। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया। 39 वर्षीय आरोपी मुकेश उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएड़ा का निवासी है।

दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे में किया लूट का पदार्फाश, तीन आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 11 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली पुलिस ने 37 .5 लाख रुपए की ह्लखुद रची गईह्व लूट की घटना को 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पीड़ित कंपनी के दो कर्मचारी भी शामिल हैं और लूटी गई लगभग पूरी रकम बरामद कर ली है।

नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ओर से बताया गया कि यह मामला एक एडवरटाइजिंग और अखबार पब्लिशिंग कंपनी के दो कर्मचारियों द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर रची गई साजिश से जुड़ा है। उन्होंने क्लाइंट्स से इकट्ठा किए गए कैश को ले जाते समय लूट का नाटक किया था। पुलिस ने बताया कि इस ऑपरेशन में तीन आरोपियों अभिषेक (26), योगेश (26) और विपिन (29) को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी आरोपियों को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं।

मौत को मात देकर स्वस्थ हुआ किशोर

नई दिल्ली, 11 जुलाई (वेब वार्ता)। करीब आठ महीने तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद 13 वर्षीय लक्षित ने आखिरकार स्वस्थ होकर अपने घर वापसी कर ली। गिलियन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) जैसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे लक्षित का इलाज दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में हुआ। इलाज के दौरान उसे तीन बार कार्डियक अरेस्ट आया और करीब तीन महीने तक वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। डॉक्टरों ने इसे अस्पताल के सबसे चुनौतीपूर्ण मामलों में से एक बताया है।

बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि लक्षित को पहले जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर उसे स्वामी दयानंद अस्पताल रेफर किया गया। जांच में पता चला कि उसे गिलियन-बैरे सिंड्रोम है। यह ऐसी बीमारी है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली नसों पर हमला कर देती है। इससे मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। डॉक्टरों के अनुसार लक्षित की सांस लेने की क्षमता खत्म होने लगी थी, इसलिए उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। लंबे समय तक सांस दिलाने के लिए ट्रेक स्टॉमी भी करनी पड़ी।

दिल्ली : लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी निकली अफवाह

पुलिस कॉलर की तलाश में जुटी

नई दिल्ली, 11 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने लाल किले की गहन तलाशी ली। इस दौरान, कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह धमकी मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में आए एक फोन कॉल से मिली थी, जिसमें कॉलर ने लाल किले को उड़ाने का दावा किया था। मुंबई पुलिस ने तुरंत यह जानकारी दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को दी, जिसने नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस को सुरक्षा उपाय शुरू करने के लिए अलर्ट किया।

अलर्ट मिलने के तुरंत बाद पुलिसकर्मी, बम निरोधक दस्ते और अन्य सुरक्षा टीमें लाल किले पहुंचीं और परिसर की गहन जांच-पड़ताल की। जांच के बाद अधिकारियों को कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। बाद में अधिकारियों ने बम की धमकी को अफवाह करार दिया। फिलहाल, अधिकारी कॉलर का पता लगाने और इस धमकी के पीछे के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि यह धमकी लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के कुछ महीनों बाद आई है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने विस्फोटक से लदी हुंडई आई20 के ड्राइवर की पहचान उमर-उन-नबी के रूप में की थी, जो फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत कश्मीरी डॉक्टर था।

विस्फोट उसी दिन हुआ था, जब सुरक्षा एजेंसियों ने राष्ट्रीय राजधानी से लगभग 50 किलोमीटर दूर हरियाणा के फरीदाबाद में एक जगह से अमोनियम नाइट्रेट सहित लगभग 2,900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया था। जांच टीमों को संदेह था कि आरोपी ने वाहन में विस्फोट तब किया, जब उसके दो कथित साथियों मुजम्मिल शकील और आदिल राथर को गिरफ्तार कर लिया गया और विस्फोटक जब्त कर लिए गए।मई में एक अन्य बड़े आतंकवाद-रोधी अभियान में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई और भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से कथित तौर पर जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच अधिकारियों के अनुसार, आरोपी कथित तौर पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों, बिजली संयंत्रों, परमाणु सुविधाओं और सुरक्षा कर्मियों सहित प्रमुख प्रतिष्ठानों पर हमले की योजना बना रहे थे।

गृह मंत्री ने किया एनडीएमसी की हाई-टेक, डिजिटल पुस्तकालय का उद्घाटन

पुस्तकालयों में जुटने वाली युवाओं की भीड़ तय करती है देश का भविष्य: अमित शाह

नई दिल्ली, 11 जुलाई (वेब वार्ता)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा उद्यान मार्ग स्थित अत्याधुनिक लोकनायक जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य कृषि, बाजार या उद्योग से नहीं, बल्कि उसके पुस्तकालयों में आने वाले युवाओं की संख्या से तय होता है। उन्होंने पुस्तकालयों को ज्ञान, विवेक और राष्ट्र निर्माण का सबसे सशक्त माध्यम बताते हुए युवाओं से पढ़ने की आदत विकसित करने का आह्वान किया।

लोकार्पण समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष केशव चंद्र, उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल, परिषद सदस्य डी.पी. सिंह, अनिल वाल्मीकि, सरिता तोमर तथा परिषद के सचिव राहुल सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि राष्ट्र को समृद्ध, आत्मनिर्भर और वैभवशाली बनाने वाली प्रत्येक गतिविधि का आधार ज्ञान और विवेक होता है तथा यह संस्कार पुस्तकालयों से ही प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को एक बार पुस्तकालय से अवश्य जुड़ना चाहिए। पढ़ने की आदत विकसित होते ही सही और गलत का विवेक स्वत: विकसित होने लगता है।

अमित शाह ने अपने बचपन का अनुभव साझा करते हुए बताया कि जिस छोटे कस्बे में उनका जन्म हुआ, वहां का समृद्ध पुस्तकालय उनके व्यक्तित्व निर्माण का आधार बना। उन्होंने कहा कि बाल साहित्य से प्रारंभ हुई उनकी अध्ययन यात्रा धीरे-धीरे वेदों, उपनिषदों और गंभीर साहित्य तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि पुस्तकें मनुष्य के विचारों को दिशा देती हैं और जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी विषय पर बोलने से पहले सोचने की आवश्यकता होती है और सोचने से पहले पढ़ना आवश्यक है। यह संस्कार केवल पुस्तकालयों से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय ज्ञान के सागर में उतरने का साहस देता है और वहां से प्राप्त अनुभव व्यक्ति के व्यक्तित्व, समाज और राष्ट्र को नई दिशा प्रदान करते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र में संचालित पुस्तकालय अभियान का उल्लेख करते हुए बताया कि वहां लगभग प्रत्येक गांव में पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं, जिनमें हजारों पुस्तकें उपलब्ध हैं। इन पुस्तकालयों को एक मुख्य पुस्तकालय से जोड़ा गया है, जहां सवा लाख से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसके साथ ही चलित पुस्तकालय वाहनों की व्यवस्था भी की गई है, जिनके माध्यम से बच्चों की मांग के अनुसार पुस्तकें गांवों तक पहुंचाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि सभी पुस्तकालयों को विद्यालयों से जोड़ने का प्रयास किया गया है ताकि विद्यार्थियों में अध्ययन की संस्कृति विकसित हो सके। अमित शाह ने दिल्ली सरकार से आग्रह किया कि राजधानी के सभी सार्वजनिक पुस्तकालयों को आपस में जोड़ा जाए और विद्यालयों को उनसे जोड़ने की ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने पुस्तकालय प्रबंधन से भी आसपास के विद्यालयों के विद्यार्थियों को पुस्तकालय से जोड़ने और उन्हें नियमित अध्ययन के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर स्थापित यह पुस्तकालय युवाओं के लिए ज्ञान और चिंतन का नया केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि यहां युवा अपनी रुचि के विषयों का अध्ययन कर उन महान व्यक्तित्वों के विचारों से परिचित हो सकेंगे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित किया। अमित शाह ने बताया कि पुस्तकालय में 30,000 से अधिक मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध हैं। शोधार्थियों के लिए पृथक अध्ययन व्यवस्था, आधुनिक सभागार, अध्ययन कक्ष, बाल अनुभाग, अनुसंधान केंद्र तथा ई-पुस्तकालय जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि यहां एक करोड़ से अधिक डिजिटल पुस्तकों तक नि:शुल्क पहुंच उपलब्ध होगी। पुस्तकालय में नि:शुल्क अंतरजाल सुविधा, अत्याधुनिक पुस्तक प्रबंधन व्यवस्था तथा राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय से भी जुड़ाव सुनिश्चित किया गया है।

दिल्ली सरकार की योजनाएं केवल दावों तक सीमित : हाजी जरीफ

नई दिल्ली, 11 जुलाई (वेब वार्ता)। कबीर नगर वार्ड के निगम पार्षद हाजी जरीफ ने दिल्ली सरकार की 'मिशन सक्षम' और 'मिशन कायाकल्प' योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की अधिकांश घोषणाएं केवल दावों तक सीमित रहती हैं और उनका अपेक्षित प्रभाव धरातल पर दिखाई नहीं देता।

हाजी जरीफ ने कहा कि सरकार सरकारी विद्यालयों के आधुनिकीकरण और नई सुविधाओं के दावे कर रही है, लेकिन वास्तविकता में अनेक विद्यालय अब भी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। उनका आरोप है कि पहले घोषित कई योजनाओं का अपेक्षित परिणाम भी सामने नहीं आया है।

पौधे लगाना नहीं, उन्हें जीवित रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी: विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली, 11 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वृक्षारोपण केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी वृक्षारोपण अभियान की सफलता लगाए गए पौधों की संख्या से नहीं, बल्कि उनके जीवित रहकर विकसित होने से तय होती है। उन्होंने नागरिकों से पौधे लगाने के साथ-साथ उनकी नियमित देखभाल और संरक्षण का भी संकल्प लेने का आह्वान किया।

विजेंद्र गुप्ता शनिवार को रोहिणी सेक्टर-14 स्थित चित्रगुप्त पार्क में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संपूर्णा और भारतीयम ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित मेगा वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे।

अभियान के दौरान लगभग 500 देशी जामुन के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ दिल्ली के निर्माण में जनभागीदारी को सशक्त बनाना था।

इस अवसर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी, पार्षद, रोहिणी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, भारतीयम ट्रस्ट, व्हाइट लोटस, संपूर्णा के प्रतिनिधि, पर्यावरणविद, स्वयंसेवक तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने हरित और स्वच्छ दिल्ली के निर्माण में सक्रिय सहयोग देने का संकल्प व्यक्त किया। अपने संबोधन में विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि निरंतर जनसहभागिता और दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रयासों के कारण रोहिणी आज दिल्ली के सबसे हरित क्षेत्रों में शामिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि चित्रगुप्त पार्क से प्रारंभ हुआ यह अभियान प्रत्येक घर तक पहुंचना चाहिए और इसे जनआंदोलन का स्वरूप दिया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक नागरिक वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ सकें। उन्होंने स्थानीय प्रजातियों के महत्व पर बल देते हुए कहा कि नीम और जामुन जैसे देशी वृक्ष स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आग्रह पर आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी दो प्रमुख ट्रेनें

नई दिल्ली, 11 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के प्रयासों से उत्तर और पश्चिम दिल्ली के लाखों रेल यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर दो महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे हिमाचल प्रदेश जाने वाले पर्यटकों के साथ-साथ पंजाब के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भी काफी सुगमता रहेगी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भेजे अपने पत्र में बताया कि उनके द्वारा भेजे गए अनुरोध पत्र के संदर्भ में आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर दो ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

स्वीकृति के अनुसार गाड़ी संख्या 14331 दिल्ली-कालका एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 14053 दिल्ली-दौलतपुर चौक हिमाचल एक्सप्रेस अब आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर भी रुकेंगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस निर्णय पर प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों की दैनिक जरूरतों और जनसुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर इन दोनों ट्रेनों के ठहराव से उत्तर व पश्चिम दिल्ली के निवासियों का समय बचेगा। यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी और उन्हें नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाने की अतिरिक्त परेशानी से राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली-कालका एक्सप्रेस के आदर्श नगर में ठहरने से कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ और कालका की यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले पर्यटकों के लिए भी यह सुविधा अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। इसी प्रकार दिल्ली-दौलतपुर चौक हिमाचल एक्सप्रेस के ठहराव से कुरुक्षेत्र, फतेहगढ़ साहिब, आनंदपुर साहिब तथा हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। विशेष रूप से श्री फतेहगढ़ साहिब और श्री आनंदपुर साहिब जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की यात्रा अब उत्तर और पश्चिम दिल्ली के लोगों के लिए पहले की तुलना में अधिक सरल और सुगम हो जाएगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार जनहित से जुड़े प्रत्येक विषय पर केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर इन दोनों ट्रेनों के ठहराव की स्वीकृति इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

आधुनिक शिक्षा सुविधाओं से सशक्त होंगे सरकारी विद्यालय : रोमेश चंद गुप्ता

नई दिल्ली, 11 जुलाई (वेब वार्ता)। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति के पूर्व चेयरमैन एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व शाहदरा जिला महासचिव रोमेश चंद गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य सरकारी विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और तकनीक के समन्वय से विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य के अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार गांव स्थित राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 'सक्षम' कार्यक्रम के तहत कई आधुनिक सुविधाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्मार्ट शौचालय, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी एवं गणित नवाचार प्रयोगशाला, आधुनिक संगणक प्रयोगशाला, डिजिटल कक्षाएं तथा छात्राओं के स्वास्थ्य से जुड़े विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

राम मंदिर चंदा मामले की फोरेंसिक जांच हो, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ें : कांग्रेस

नई दिल्ली, 11 जुलाई (वेब वार्ता)। कांग्रेस ने अयोध्या स्थित राम मंदिर के चंदा प्रबंधन से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में फोरेंसिक लेखा परीक्षण कराने की मांग करते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि यह मामला केवल कुछ कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी निष्पक्ष और व्यापक जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ने की भी मांग की।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, वरिष्ठ प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव तथा महासचिव अनिल भारद्वाज ने यह मांग उठाई।

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राम मंदिर के चंदे से जुड़े कथित गबन को किसी छोटी प्रशासनिक चूक के रूप में नहीं देखा जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि यह एक सुनियोजित घटना प्रतीत होती है, जिसकी गहन जांच आवश्यक है। उनका कहना था कि प्रारंभिक स्तर पर सामने आई जानकारी पूरे मामले की केवल एक झलक है और इसकी फोरेंसिक लेखा जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार 27 अप्रैल से 5 जून के बीच लगभग 40 दिनों में चंदा गणना कक्ष से कथित चोरी की 70 घटनाएं सामने आईं और इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिंघवी ने सवाल उठाया कि यदि चंदा प्रबंधन की जिम्मेदारी शीर्ष स्तर पर तय थी, तो जांच का दायरा केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक ही क्यों सीमित रखा गया है।

...समान रूप से की कार्रवाई की मांग

देवेंद्र यादव ने वर्ष 1958 में राजस्थान के श्रीनाथ मंदिर से जुड़े एक मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप से न्यायिक जांच कराई गई थी। उनका कहना था कि वर्तमान मामले में भी पारदर्शी और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। अनिल भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई कर बड़े स्तर की जवाबदेही से बचने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच और सभी जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध समान रूप से कार्रवाई की मांग करती है।

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि मंदिर ट्रस्ट और बैंक के बीच बनी प्रक्रिया के अनुसार दान पेटियों को अधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खोलने, प्रत्येक पेटी की अलग-अलग गणना करने, बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने तथा प्रवेश और निकास के समय जांच की व्यवस्था थी। उन्होंने सवाल किया कि यदि सभी व्यवस्थाएं लागू थीं तो कथित अनियमितताएं कैसे हुईं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह मामला केवल धनराशि का नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर कब अपनी प्रतिक्रिया देंगे, क्या मामले में सभी जिम्मेदार व्यक्तियों की निष्पक्ष जांच होगी तथा क्या केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई कर मामले को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। उनका आरोप था कि यदि मंदिर के चंदे में अनियमितता हुई है तो इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस मामले पर सार्वजनिक रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

दिल्ली सरकार ने अभय वर्मा को बनाया मुख्य प्रवक्ता, अनिल शर्मा और हरीश खुराना को भी मिली जिम्मेदारी

नई दिल्ली, वेब वार्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधायक अभय कुमार वर्मा को दिल्ली सरकार का मुख्य प्रवक्ता तथा विधायक अनिल कुमार शर्मा और हरीश खुराना को सरकार का प्रवक्ता नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार ने पारदर्शी, जवाबदेह और जनकेंद्रित शासन के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के माध्यम से सरकार के नीतिगत निर्णयों, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की आधिकारिक एवं तथ्यपरक जानकारी समयबद्ध तरीके से नागरिकों और मीडिया तक पहुंचाई जा सकेगी। मुख्य प्रवक्ता और प्रवक्ता के रूप में नियुक्त जनप्रतिनिधि विभिन्न समसामयिक विषयों पर दिल्ली सरकार का अधिकृत पक्ष प्रस्तुत करेंगे। वे सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों, नीतिगत पहलों तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर आधिकारिक जानकारी साझा करेंगे, मीडिया के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर सरकार की ओर से तथ्यों और निर्णयों का स्पष्टीकरण भी देंगे। इसके साथ ही वे विभिन्न विभागों से प्राप्त अधिकृत सूचनाओं के आधार पर सरकार का दृष्टिकोण जनता तक पहुंचाने का दायित्व निभाएंगे।

...और मजबूत होगी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रभावी जनसंवाद सुशासन का महत्वपूर्ण आधार है। मुख्य प्रवक्ता और प्रवक्ताओं की नियुक्ति से सरकार एवं नागरिकों के बीच संवाद और अधिक सशक्त होगा तथा शासन से संबंधित प्रामाणिक, पारदर्शी और समयबद्ध जानकारी जनसामान्य तक सुव्यवस्थित रूप से पहुंच सकेगी। इससे सरकार की जनहितकारी पहलों के संबंध में स्पष्ट एवं अधिकृत सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी और मजबूत होगी।

ई20 ईंधन के मुद्दे पर केजरीवाल पहुंचे पेट्रोल पंप, लोगो से किया संवाद

नई दिल्ली, 11 जुलाई (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को राजधानी के एक पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन का दौरा कर आम लोगों से बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि इथेनॉल 20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन चालकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि सरकार ई20 को लेकर लगातार झूठ बोल रही है।

आधी रात को ब्लू लाइन पर निकले डीएमआरसी के एमडी

स्टेशनों पर विकास कार्यों का लिया जायजा

नई दिल्ली, 11 जुलाई (वेब वार्ता)। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर यात्रियों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात अचानक निरीक्षण पर निकल पड़े। उन्होंने आधी रात से सुबह पांच बजे तक द्वारका सेक्टर-21 से नोएडा सिटी सेंटर तक कई प्रमुख मेट्रो स्टेशनों का दौरा कर चल रहे निर्माण और आधुनिकीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि विकास कार्यों के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

डीएमआरसी के अनुसार, रात्रिकालीन निरीक्षण शुक्रवार रात 12 बजे द्वारका सेक्टर-21 मेट्रो स्टेशन से शुरू हुआ। इसके बाद डॉ. विकास कुमार ने द्वारका सेक्टर-14, द्वारका मोड़, राजौरी गार्डन, करोल बाग, आर.के. आश्रम, इंद्रप्रस्थ और नोएडा सिटी सेंटर सहित ब्लू लाइन के कई प्रमुख स्टेशनों का निरीक्षण किया। सुबह करीब पांच बजे निरीक्षण समाप्त हुआ।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशनों पर चल रहे री-मॉडलिंग कार्य, नए एस्केलेटर लगाने, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन (एएफसी) गेट के पुनसंरेखण (रियलाइनमेंट) और अन्य यात्री सुविधाओं से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी हों और काम के दौरान यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। डॉ. विकास कुमार ने कहा कि दिल्ली मेट्रो की प्राथमिकता केवल सेवाओं का विस्तार करना नहीं, बल्कि मौजूदा नेटवर्क पर यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं करने और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए। डीएमआरसी अधिकारियों ने बताया कि परिचालन वाली मेट्रो लाइनों पर अधिकांश रखरखाव और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य केवल रात के समय किए जाते हैं, जब मेट्रो सेवाएं बंद रहती हैं। इससे दिन में लाखों यात्रियों की आवाजाही प्रभावित नहीं होती और नियमित सेवाएं बिना किसी व्यवधान के जारी रहती हैं।

संक्षिप्त वार्ता

डॉ अवंतिका बंसल ने एम.एस. ईएनटी स्मातकोत्तर परीक्षा में प्राप्त किया स्वर्ण

वेब वार्ता, कानपुर। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल (जीएसवीएम) कॉलेज, कानपुर की डॉ. अवंतिका बंसल ने उत्तर प्रदेश राज्य एम.एस. ईएनटी स्मातकोत्तर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक अर्जित करके कॉलेज का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। कॉलेज के प्राचार्य एवं डीन प्रो. डॉ. संजय काला ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ईएनटी विभाग को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

डॉ अवंतिका बंसल ने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश राज्य एम.एस. ईएनटी स्सातकोत्तर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। यह उत्कृष्ट उपलब्धि डॉ. अवंतिका की असाधारण शैक्षणिक प्रतिभा, अथक परिश्रम, दृढ संकल्प तथा ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी (ईएनटी) विषय के प्रति उनकी समर्पित निष्ठा का प्रमाण है। उनकी यह सफलता संस्थान, ईएनटी विभाग, उनके गुरुजनों, सहपाठियों तथा परिवार के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। इस अवसर पर ईएनटी विभाग के समस्त संकाय सदस्य, रेज़िडेंट चिकित्सक एवं कर्मचारीगण ने डॉ. अवंतिका बंसल को इस प्रतिष्ठित उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी।

25 हजार का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। थाना अतरौली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस के अनुसार 12 जून 2026 को थाना अतरौली में इरफान पुत्र अल्ताफ, निवासी ग्राम तेतारपुर, थाना मुसाफिरखाना, जनपद अमेठी समेत आठ आरोपियों के विरुद्ध गिरोह बनाकर समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 3(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। शनिवार को थाना अतरौली पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी इरफान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट, पशु क्रूरता अधिनियम, आर्म्स एक्ट तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक विनोद कुमार शर्मा, उपनिरीक्षक ज्ञान सिंह, हेड कांस्टेबल शैलेन्द्र प्रताप सिंह तथा कांस्टेबल शिवम कुमार शामिल रहे।

महिला परिधान सिलाई प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित

वेब वार्ता/हरदोई

बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) ने जनपद की 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग की बेरोजगार युवतियों के लिए 31 दिवसीय नि:शुल्क महिला परिधान सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। संस्थान के निदेशक विक्रांत ओझा ने बताया कि प्रशिक्षण 22 जुलाई 2026 से प्रारंभ होगा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान बेसिक सिलाई के साथ-साथ मॉडर्न ड्रेसेज, फैंसी सूट, स्कूल ड्रेस तथा सिलाई मशीन की बेसिक रिपेयरिंग का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में आवास एवं भोजन की व्यवस्था पूर्णत: नि:शुल्क रहेगी।

पौधरोपण महायज्ञ के चलते रविवार को स्थगित रहेगा जनता दर्शन

गोरखपुर, वेब वार्ता

उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ रिकॉर्ड पौधारोपण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 12 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाले पौधारोपण महायज्ञ 2026 में अधिकाधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रविवार को श्री गोरखनाथ मंदिर में प्रात:काल जनता दर्शन का कार्यक्रम स्थगित रहेगा। यह जानकारी श्री गोरखनाथ मंदिर कार्यालय की तरफ से शनिवार को दी गई है। जारी सूचना के अनुसार, रविवार 12 जुलाई को प्रात: 7:45 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के समीप पौधा लगाकर पौधरोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे।

नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा...'

कुशीनगर से सीएम योगी का विपक्ष पर सीधा प्रहार

दियारा को मिलेगा 800 करोड़ का पुल

कुशीनगर से शीघ्र शुरू होगी उड़ान, गया और जेवर से जुड़ेगा

वेब वार्ता, ममता तिवारी

कुशीनगर। जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर, रामकोला हाटा विधानसभा क्षेत्र की 525 करोड़ की 464 परियोजनाओं का शनिवार को लोकार्पण व शिलान्यास करते हुए विपक्ष को विकास और कानून व्यवस्था पर घेरते हुए सीधा हमला बोला। कहा कि, पहले की सरकार के पास नीयत थी न नीति थी। सोच ही लकवाग्रस्त थी, ऐसे में विकास की बात ही बेमानी थी।

इस दौरान टेकुआटार में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सपा पर हमला बोला और कहा कि, पहले उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर दंगे होते थे, अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। बिना राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जिक्र करते हुए कहा कि मंदिरों पर कब्जा करने वाले अयोध्या, काशी और मथुरा के बारे में कैसे सोच सकते हैं। धर्म आस्था पर आज हमें आइना दिखाने वाले अपना चेहरा देखें।

मुख्यमंत्री योगी ने कुशीनगर की इंसेफेलाइटिस से मासूमो के बचपन छिनने व मुसहरों की मौत का उदाहरण देते पूर्व की सरकारों को कठघरे में खड़ा किया तो कहा कि, अब इंसेफेलाइटिस से बचपन छिनता है और न कोई प्रदेश में भूख से मरता है। अब आवास, बिजली, गैस कनेक्शन, उपचार व रोजगार संग विकास की बात होती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, पश्चिम एशिया संकट से दुनिया में मची उथल-पुथल के चलते नए नए एयरक्राफ्ट नहीं आ सके, जिससे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू नहीं हो सकी। शीघ्र ही यहां से उड़ान शुरू होगी और गया और जेवर को जोड़ जाएगा। सरकार पूरी तरह संजीदा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारायणी उस पार दियारा के गांवों की दुर्दशा के लिए पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि डीपीआर बन रहा है। शीघ्र ही नारायणी पर 800 करोड़ का पुल बनेगा। दियारा के सभी गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगें। अंतिम व्यक्ति का विकास ही हमारी सरकार की सोच है। इस पर हम इमानदारी से कार्य भी कर रहे हैं।

ईपीएफओ एमनेस्टी स्कीम-2026 छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए एक एकमुश्त राहत योजना

वेब वार्ता, कानपुर। सभी नियोक्ताओं, स्टेकहोल्डर्स और आम जनता का ध्यान केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एमनेस्टी स्कीम, 2026 यानी माफी योजना की ओर आकर्षित किया जाता है। यह स्कीम इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट चलाने वाले संस्थानों को अपनी स्थिति को रेगुलर करने (नियमों के अनुरूप करने) के लिए छह महीने का समय देती है। फाइनेंस एक्ट, 2026 ने मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड को नियंत्रित करने वाले इनकम टैक्स फ्रेमवर्क को श्एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट, 1952श के कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों के अनुरूप बना दिया है। इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत मान्यता केवल उन्हीं प्रोविडेंट फंड को मिलेगी जिन्हें श्एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट, 1952 की धारा 17 के तहत छूट मिली है। ऐसे संस्थानों को एक्ट की धारा 17 और श्कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 की धारा 143 के तहत पिछली तारीख से एमनेस्टी (माफी) दी जाएगी।

यह स्कीम उन संस्थानों पर लागू होती है जो इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट चला रहे हैं, लेकिन उनके पास संबंधित सरकार – केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो – से छूट का औपचारिक नोटिफिकेशन नहीं है। यह स्कीम नोटिफिकेशन की तारीख से छह (6) महीने की अवधि के लिए मान्य है। इस स्कीम का नोटिफिकेशन 29 जून, 2026 को जारी किया गया है। जिसमें योग्य संस्थान आते है। वे संस्थान जो ट्रस्ट को पिछली तारीख से रेगुलर करवाना चाहते हैं और जिन्होंने पहले ही बिना छूट वाले संस्थान के तौर पर नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है या जो बिना छूट वाले संस्थान के तौर पर भविष्य में नियमों का पालन करने का विकल्प चुन रहे हैं। साथ ही वे संस्थान जो ट्रस्ट को पिछली तारीख से रेगुलर करवाना चाहते हैं और जो श्कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 के तहत छूट प्राप्त संस्थान के तौर पर काम करना जारी रखना चाहते हैं।

विश्व जनसंख्या दिवस पर निकली जागरूकता रैली, 18 जुलाई तक चलेगा अभियान

वेब वार्ताद्ध लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर शनिवार को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला पुरुष चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. चंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. चंद्र कुमार ने कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य लोगों को परिवार नियोजन के महत्व के प्रति जागरूक करना तथा स्वस्थ, समृद्ध एवं खुशहाल परिवार की अवधारणा को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि छोटा परिवार न केवल मां एवं बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य की आधारशिला है, बल्कि परिवार के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

रैली के माध्यम से आमजन को छोटे परिवार के लाभ, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन के स्थायी एवं अस्थायी साधनों के बारे में जागरूक किया गया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भवनाथ पांडे ने बताया कि विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में जनपद में 11 से 18 जुलाई तक परिवार नियोजन जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के दौरान आशा, एएनएम एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर योग्य दंपतियों को परिवार नियोजन के विभिन्न सुरक्षित एवं प्रभावी साधनों, उनके लाभ तथा छोटे परिवार के महत्व के बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने बताया कि जिला महिला चिकित्सालय, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर परिवार नियोजन के स्थायी एवं अस्थायी साधन उपलब्ध हैं। इच्छुक लाभार्थी अपने निकटतम सरकारी स्वास्थ्य संस्थान पर नि:शुल्क परिवार नियोजन सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि वे परिवार नियोजन के उपलब्ध साधनों की जानकारी प्राप्त करें और अपनी आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग कर स्वस्थ एवं खुशहाल परिवार के निर्माण में सहयोग करें।

कार्यक्रम में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मधुलिका शुक्ला, परिवार नियोजन काउंसलर गरिमा शुक्ला, स्टाफ नर्स शशि देवी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी इंद्रभूषण सिंह, एफपीएलएमआईएस प्रबंधक किन्दरलाल, स्त्री क्लिनिक संस्था से स्नेहा मिश्रा, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं निर्मला नर्सिंग इंस्टीट्यूट के छात्र-छात्राएं, निर्मला नर्सिंग इंस्टीट्यूट से मृदुल पांडे सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

असम राइफल्स के जवान सत्येंद्र सिंह को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई

देवरिया 11 जुलाई। देवरिया जिले में असम राइफल्स में तैनात जवान सत्येंद्र सिंह का शनिवार को सैन्य सम्मान के साथ रामपुर कारखाना क्षेत्र के पटनवा पुल के समीप छोटी गंडक नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया। असम राइफल्स के जवानों और स्थानीय पुलिस ने उनके घर तथा घाट पर सलामी देकर अंतिम विदाई दी।

इस दौरान मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल स्वजन को सांत्वना दी।

रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के रामपुर चंद्रभान गांव निवासी 36 वर्षीय सत्येंद्र सिंह पुत्र रमेश सिंह की सात वर्ष पूर्व असम राइफल्स में नियुक्ति हुई थी। वर्तमान में उनकी तैनाती शिलांग में थी। आठ जुलाई की रात करीब 10 बजे उनके सीने में अचानक दर्द हुआ। उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृत्यु की सूचना मिलते ही स्वजन में मातम छा गया।

शनिवार को सत्येंद्र सिंह का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो स्वजन के साथ ही वहां मौजूद लोग फफक पड़े। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्र के लोग पहुंचे। इसके बाद पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए पटनवा पुल स्थित छोटी गंडक नदी के तट पर ले जाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।

हर व्यक्ति आंखे हो गईं नम

सत्येंद्र सिंह की पत्नी सिमला देवी, 10 वर्षीय पुत्री दिशा और नौ वर्षीय पुत्र विराट सिंह का रो-रोकर बुरा हाल था। परिवार के करुण क्रंदन से वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं।

नो-एंट्री में दौड़ रहे बालू लदे ट्रैक्टर, सुसुवाही में बढ़ा हादसों का खतरा, लोगों में आक्रोश

वाराणसी, 11 जुलाई (वेब वार्ता)। शहर में नो-एंट्री नियमों के बावजूद भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होने से लोगों की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सुसुवाही क्षेत्र में बालू और निर्माण सामग्री से लदे ट्रैक्टर दिन के समय भी धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे स्थानीय नागरिकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन और संबंधित विभागों की लापरवाही के कारण इस मार्ग पर हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है।

शनिवार सुबह सुसुवाही क्षेत्र में एक बालू से लदा ट्रैक्टर तेज रफ्तार से गुजरता दिखाई दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन की गति इतनी अधिक थी कि यदि अचानक कोई राहगीर, स्कूली बच्चा या दोपहिया चालक सामने आ जाता तो गंभीर हादसा हो सकता था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही पर चिंता जताते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सुसुवाही की सड़कें घनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरती हैं, जहां सुबह और शाम के समय स्कूली बच्चों, छात्रों, बुजुर्गों और नौकरीपेशा लोगों की आवाजाही सबसे अधिक रहती है। इसके बावजूद बालू लदे ट्रैक्टर निर्धारित समय का पालन किए बिना आबादी वाले क्षेत्रों से गुजर रहे हैं। इससे सड़क पर चलने वाले लोगों में हमेशा भय का माहौल बना रहता है। स्थानीय नागरिकों के मुताबिक, इस मार्ग पर पहले भी ट्रैक्टरों की चपेट में आने से कई लोग घायल हो चुके हैं। इसके बावजूद नो-एंट्री नियमों का उल्लंघन लगातार जारी है।

समय पर इलाज न मिलने से सर्पदंश पीड़िता की मौत, तीन मासूम बच्चों से उठा मां का साया

वेब वार्ता, हरदोई। थाना कासिमपुर क्षेत्र के ग्राम बेहसार में सर्पदंश की शिकार एक महिला की समय पर उपचार न मिलने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और तीन मासूम बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया।

जानकारी के अनुसार, गांव निवासी किसान राजकिशोर की 35 वर्षीय पत्नी संगीता देवी शुक्रवार रात बारिश के कारण छत से नीचे आकर जमीन पर लेट गई थीं। इसी दौरान उन्हें सांप ने काट लिया। परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक और देसी उपचार के चक्कर में इधर-उधर भटकते रहे, जिससे काफी कीमती समय निकल गया। बाद में महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कछौना ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां से चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ भेज दिया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।

सरकार द्वारा सर्पदंश के उपचार के लिए सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी-स्नेक वेनम (एएसवी) उपलब्ध कराने की व्यवस्था किए जाने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की

कमी के कारण कई लोग आज भी झाड़-फूंक और घरेलू उपचार पर भरोसा कर बहुमूल्य समय गंवा देते हैं। घटना की सूचना पर राजस्व विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। ग्राम प्रधान अर्जुन वर्मा ने बताया कि मृतका के परिजनों को मुख्यमंत्री दैवीय आपदा राहत योजना के तहत आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

नाले में गिरने से मजदूर की मौत

कानपुर, 11 जुलाई (वेब वार्ता)। पनकी थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात को नाले में गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। शुरूआती जांच में सामने आया है कि मृतक नशे की हालत में घर लौट रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पड़ताल में जुट गई है। घटना रतनपुर स्थित काशीराम कॉलोनी के पास की है। यहां रहने वाले हरिशंकर (50) मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। रात वह घर लौट रहे थे। रास्ते में नाला पार करते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वह पानी से भरे नाले में जा गिरे। नाले में पानी अधिक होने के कारण वह बाहर नहीं निकल सके।

जलालाबाद में तेज रफ्तार कार ने स्कूली बच्चों से भरे ई-रिक्शा को मारी टक्कर, 10 बच्चे घायल

वेब वार्ता, शाहजहांपुर। जलालाबाद नगर में शनिवार सुबह करीब साढ़े सात बजे एक तेज रफ्तार कार ने स्कूली बच्चों से भरे ई-रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 10 बच्चे घायल हो गए, टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।

जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चों को लेकर ई-रिक्शा सरस्वती विद्या मंदिर जलालाबाद आ रहा था। बारह पत्थर चौराहे पर

चालक ने सड़क किनारे खड़े 3 अन्य बच्चों को बैठाने के लिए ई-रिक्शा रोका था। इसी दौरान फरुर्खाबाद की ओर से आ रही

तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि ई-रिक्शा पलट गया और बच्चे सड़क पर जा गिरे। चीख-पुकार सुनकर राहगीर और दुकानदार दौड़े। बारह पत्थर चौकी पुलिस ने घायलों को तुरंत सीएचसी जलालाबाद पहुंचाया। सूचना पर थाना प्रभारी अरविंद सिंह चौहान भी अस्पताल पहुंचे। घायलों में शुभांशु, दीपक, शिवम, प्रयंजुल, दिव्यांशी, सौरभ, अर्पित, आयुष राजपूत, सूर्यांश, ज्योति वर्मा और रूपेश शामिल हैं। इनमें शुभांशु, दीपक, प्रयंजुल और दिव्यांशी के सिर में चोट है। पुलिस ने फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी है।

शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा दी गई: सीएम योगी

ममता तिवारी/वेब वार्ता

कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कुशीनगर में 525 करोड़ रुपये की लागत वाली 464 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग युवाओं का रोजगार छीनने का काम करते थे, वे अयोध्या, मथुरा और काशी जैसे आस्था केंद्रों के विकास के बारे में कभी नहीं सोच सकते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान मंदिरों के नाम पर मिलने वाली धनराशि का दुरुपयोग किया जाता था, जबकि वर्तमान सरकार मंदिरों के पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने विकास और सुशासन को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया है। उन्होंने कहा कि कुशीनगर में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि और संपर्क व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले कुशीनगर दिमागी बुखार, पलायन और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, लेकिन सरकार की प्रभावी रणनीति, स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, टीकाकरण, स्वच्छता और जनजागरूकता अभियानों के कारण इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय तक उपेक्षित रहे मुसहर समाज के परिवारों को सरकार ने मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इन परिवारों को पक्के आवास, भूमि के पट्टे, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, नि:शुल्क राशन, रसोई गैस कनेक्शन और विद्युत सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे उनमें आत्मविश्वास और सम्मान की भावना बढ़ी है।

शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया है। उन्होंने बताया कि बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों तथा रसोइयों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की नगदरहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही दुर्घटना बीमा का लाभ भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को जल्द ही जेवर और गया से जोड़ने की तैयारी चल रही है। नए विमान उपलब्ध होने के बाद यहां से हवाई सेवाओं का और विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खड्डा क्षेत्र में नारायणी नदी पर लगभग 800 करोड़ रुपये की लागत से नया पुल बनाया गया है तथा रामकोला-कसया मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्ताव भी शीघ्र स्वीकृत किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मंदिरों के सौंदर्यीकरण और पुनरुद्धार का कार्य कराया जा रहा है। कुशीनगर में रामाभार स्तूप और हिरण्यवती नदी के किनारे भी पर्यटक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना से युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और इसी शैक्षणिक सत्र से प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू होगी। केला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखी गई है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 110 वर्षीय राम विलास भगत और 104 वर्षीय राम प्रसाद साहनी को सम्मानित किया। उन्होंने दो बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया और कहा कि यदि बचपन सुरक्षित होगा तो देश का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों, युवाओं, किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चेक, किसान ऋण पत्र, कृषि यंत्रों की चाबी, सिलाई मशीन तथा अन्य सहायता सामग्री वितरित की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

वीजा नीति में बदलाव: भारतीयों को झटका, नौकरी-पढ़ाई पर पड़ेगा असर

वॉशिंगटन। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन रोजगार और स्टूडेंट वीजा से जुड़े कई बड़े नियमों को बदलने की तैयारी कर रहा है, जिसका सबसे बड़ा असर भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स, छात्रों और बड़ी कंपनियों पर पड़ने वाला है। ये बदलाव विशेष रूप से भारतीयों को प्रभावित करेंगे क्योंकि वे अमेरिकी वर्क और स्टूडेंट वीजा के सबसे बड़े लाभार्थियों में से हैं।

प्रस्तावित नियमों में एच-1बी वीजा, ग्रीन कार्ड प्रक्रिया, स्टूडेंट वीजा और एच-4 वीजा धारकों के वर्क परमिट को लेकर कई महत्वपूर्ण संशोधन शामिल हैं, जो आने वाले महीनों में लागू हो सकते हैं।

सबसे बड़ा झटका एच-1बी वीजा नियमों को लेकर लग सकता है, जो अगस्त में आने वाले हैं। नए नियमों के तहत, अगर कोई कंपनी अपने एच-1बी कर्मचारी को किसी तीसरी कंपनी पर काम के लिए भेजती है, तो उसके नियम बहुत सख्त कर दिए जाएंगे। कंपनियों को अब यह साबित करने के लिए ठोस सबूत और दस्तावेज देने होंगे कि कर्मचारी और कंपनी के बीच असली मालिक-कामगार का रिश्ता है और वह वहां कोई खास काम ही कर रहा है। इसके अलावा, जिन कंपनियों ने पहले नियमों का पालन नहीं किया, उनके वीजा आवेदनों की बहुत बारीकी से जांच होगी, जिससे उनके लिए वीजा प्राप्त करना और भी मुश्किल हो जाएगा। जुलाई में आने वाले एक और नियम से भारतीय आईटी आउटसोर्सिंग कंपनियों की जेब ढीली होने वाली है. अभी तक जिन कंपनियों में आधे से ज्यादा कर्मचारी एच-1बी या एल-1 वीजा वाले होते थे, उन्हें सिर्फ नया कर्मचारी रखने पर ही अलग फीस देनी पड़ती थी। लेकिन नए प्रस्ताव में तय है कि अब मौजूदा कर्मचारियों का वीजा बढ़ाने पर भी यह भारी फीस देनी होगी। इसके साथ ही, अब कंपनियों को एंट्री-लेवल के विदेशी कर्मचारियों को पहले के मुकाबले काफी ज्यादा सैलरी देनी होगी, जिससे अमेरिका में विदेशी वर्कर को नौकरी पर रखना बहुत महंगा हो जाएगा।

ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए होने वाले लेबर सर्टिफिकेशन के नियमों को भी बदला जा रहा है। साल 2004 के बाद पहली बार इस सिस्टम को पूरी तरह अपडेट किया जा रहा है। इसके तहत, अगर कोई कंपनी विदेशी कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड के लिए स्पॉन्सर कर रही है, तो उससे पहले कंपनी में छंटनी को लेकर कड़े नियम लागू होंगे, ताकि अमेरिकी नागरिकों के साथ कोई भेदभाव न हो। अमेरिका में पढ़ाई कर रहे लगभग 3.60 लाख भारतीय छात्रों के लिए भी नियम बदलने वाले हैं, जो वहां के कुल विदेशी छात्रों का 31 फीसदी हैं। अभी तक छात्र जब तक पढ़ाई करते थे, तब तक उन्हें अमेरिका में रहने की अनुमति मिल जाती थी। लेकिन अब छात्र वीजा एक तय समय के लिए ही जारी होगा, जो अधिकतम 4 साल होगा। अगर पढ़ाई लंबी खिंचती है, तो छात्रों को अमेरिकी अथॉरिटी से अलग से समय बढ़वाना होगा, जिससे प्रक्रिया जटिल और अनिश्चित हो जाएगी।

भारत के खिलाफ पाक का मददगार तुर्की पर मेहरबान हुए ट्रंप

अंकारा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को एक बड़ी राहत देने का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने साल 2020 में तुर्की पर लगाए गए अमेरिकी बैन को हटाने की बात कही। यह बैन तब लगाया गया था जब तुर्की ने रूस से एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद की थी, जिससे अमेरिका के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। यह घोषणा अंकारा में हुई, जबकि तुर्की वही देश है जिसे आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान का करीबी दोस्त माना जाता है। पूर्व में, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तुर्की के ड्रोनों की मदद से ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कई दिनों तक हमले किए थे, हालांकि भारत ने इन हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया और मुंहतोड़ जवाब दिया था। ट्रंप ने अंकारा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका तुर्की पर 2020 में लगाए गए प्रतिबंधों को हटाएगा। नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान बेस्टेपे प्रेसिडेंशियल कंपाउंड में तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन के साथ खड़े होकर ट्रंप ने इस फैसले की पुष्टि की।

संजय राउत का दावा, गडकरी को बदनाम कर रही भाजपा

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है। राउत के मुताबिक, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की छवि को खुद भारतीय जनता पार्टी नुकसान पहुंचाना चाहती है, क्योंकि गडकरी देश के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए एक बेहद मजबूत और लोकप्रिय दावेदार हैं। संजय राउत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नितिन गडकरी को बदनाम करने के पीछे कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि खुद बीजेपी के ही कुछ बड़े नेता शामिल हैं, जो उन्हें जानबूझकर एक जाल में फंसाना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को रोका जा सके।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान संजय राउत ने आरोप लगाया, गडकरी साहब को लेकर जनता के बीच जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है, उसमें उनके ही पार्टी के लोगों का हाथ है। नितिन गडकरी को बदनाम करने में और कोई नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। वे उन्हें किसी न किसी तरह से एक जाल में फंसाना चाहते हैं। राउत ने अपने दावे को मजबूती देने के लिए अतीत का हवाला देते हुए कहा, 2014 से पहले भी जब गडकरी को पार्टी अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल देने की चर्चा चल रही थी, तब भी उन्हें इसी तरह फंसाने की कोशिशें हुईं थीं। उन्होंने दोहराया कि नितिन गडकरी की लोकप्रियता अच्छी है और वे प्रधानमंत्री पद के अगले दावेदार हो सकते थे, इसीलिए भाजपा खुद ही साजिश रच रही है। राउत ने कहा, वे पीएम पद के एक मजबूत दावेदार हैं, इसलिए उन्हें इतना बदनाम कर दो कि जनता के बीच उनकी छवि खराब हो जाए। ये उनकी ही पार्टी के लोग कह रहे हैं। उनको भी सब पता है। यह पूरा विवाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ई20 पेट्रोल (20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित ईंधन) को लेकर चल रही चचाओं और आरोपों से जुड़ा है। भारत सरकार ने देश में 20 फीसदी इथेनॉल मिले हुए पेट्रोल को अनिवार्य कर दिया है, जिसके चलते सार्वजनिक रूप से खूब विरोध हो रहा है। गडकरी ने सार्वजनिक तौर पर यह चुनौती दी है कि ई20 फ्यूल से गाड़ियों में कोई खराबी नहीं आती है, लेकिन उनकी इस चुनौती के बाद बहस और तेज हो गई है।

बातचीत टूटने के बाद पीओके में तनाव, हिंसक हो सकता है आंदोलन

मुजफ्फराबाद। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में हालात एक बार फिर बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) और पाकिस्तान सरकार के बीच चल रही बातचीत पूरी तरह टूट चुकी है। अब जानकारों को हिंसक आंदोलन की आशंका है। क्योंकि संगठन ने अब दो टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गईं, तो पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। कमेटी ने सरकार को अपनी 38 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था, उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। इन मांगों में बेहतर प्रशासन, महंगाई से राहत, संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकार और गिरफ्तार कार्यकताओं की रिहाई जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। सरकार के उदासीन रवैये को देखते हुए जॉइंट कमेटी ने आगामी 15 जुलाई से रावलाकोट से मुजफ्फराबाद तक एक विशाल लॉन्ग मार्च निकालने का एलान किया है। रावलकोट जिला प्रशासन ने इस मार्च की घोषणा की पुष्टि की है और कहा है कि प्रदर्शनकारियों के कदम के अनुसार ही आगे का फैसला लिया जाएगा। आंदोलनकारी नेताओं का कहना है कि अब बातचीत का रास्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है और आंदोलन अपने सबसे निर्णायक दौर में प्रवेश कर रहा है।

तेल के संकट से बिचुमेन हुआ दोगुना महंगा और निर्माण कार्य ठप

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी ईरान युद्ध का असर अब भारत के बुनियादी ढांचे और सड़कों पर भी दिखने लगा है। आम तौर पर माना जाता है कि युद्ध से केवल पेट्रोल-डीजल के दाम प्रभावित होते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा सीधा असर देश की सड़कों के निर्माण और मरम्मत पर पड़ रहा है। वर्तमान में देश में जारी बारिश के मौसम के कारण सड़कें टूट रही हैं और उनमें गड्ढे हो रहे हैं, लेकिन बिचुमेन (डामर) की भारी किल्लत और बढ़ी हुई कीमतों के कारण इनकी समय पर मरम्मत होना मुश्किल नजर आ रहा है।

पब्लिक जिसे सामान्य बोलचाल में तारकोल कहती है, वह वास्तव में बिचुमेन होता है, जो कच्चे तेल को रिफाइनरियों में साफ करने के बाद बचे सबसे भारी और चिपचिपे हिस्से से बनता है। यही काला गाढ़ा पदार्थ सड़क बनाने में पत्थर, बजरी और मिट्टी को आपस में जोड़ने का काम करता है। भारत को हर साल अपनी सड़कों के निर्माण और रख-रखाव के लिए करीब 90 लाख टन बिचुमेन की जरूरत होती है। देश की रिफाइनरियां केवल 54 लाख टन का ही उत्पादन कर पाती हैं, जबकि बाकी का 36 लाख टन (करीब 30 से 40 प्रतिशत) हिस्सा इराक, यूएई, ईरान और ओमान जैसे देशों से मंगाना पड़ता है।

ईरान युद्ध का भारत की सड़कों पर बड़ा असर

साल के शुरूआती महीनों में ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का समुद्री मार्ग बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे बिचुमेन का आयात लगभग ठप हो गया है। इस सप्लाई चेन के टूटने से देश में बिचुमेन की भयंकर शॉर्टेज हो गई है। संकट यहीं खत्म नहीं होता; युद्ध के चलते कच्चे तेल के दाम बढ़ने से बिचुमेन की कीमतें सीधे दोगुनी हो चुकी हैं। जो बिचुमेन पहले 40 हजार रुपये प्रति टन मिलता था, वह अब 80 हजार रुपये प्रति टन के पार पहुंच चुका है।

इस भारी मूल्य वृद्धि के कारण सड़क बनाने वाले ठेकेदारों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ठेकेदारों का कहना है कि उन्हें पुराने रेट पर टेंडर मिले थे, इसलिए अब दोगुने दाम पर बिचुमेन खरीदकर काम करना उनके लिए घाटे का सौदा है। इसके चलते प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली ग्रामीण सड़कों और राज्यों के लोक निर्माण विभागों के प्रोजेक्ट्स का काम रुक गया है। यहां तक कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स की गति भी काफी धीमी हो गई है। हालांकि, भारत ने धान के भूसे से बायो-बिचुमेन बनाने का विकल्प शुरू किया है, लेकिन देश की विशाल मांग को देखते हुए अभी इसका उत्पादन बेहद कम है। यदि युद्ध लंबा खिंचता है, तो आने वाले दिनों में देश को टूटी सड़कों और जानलेवा गड्ढों से राहत मिलना नामुमकिन हो जाएगा।

अरुणाचल में सैन्य ढांचा मजबूत होने का दावा

एलएसी पर आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर

नई दिल्ली। भारत-चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से सटे अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना और वायुसेना ने अपनी परिचालन क्षमता और सैन्य ढांचे को लगातार मजबूत किया है। सीमा क्षेत्रों में सड़क, पुल और अन्य रणनीतिक आधारभूत संरचनाओं के विकास से सेना की त्वरित तैनाती और रसद व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक सुदृढ़ हुई है।

ये दावे ऐसे समय किए जा रहे हैं जबकि अरुणाचल में चीनी सेना के अंदर घुसने के आरोप तेजी से लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर जमकर बहस जारी है और तरह-तरह के कंटेंट वाले वीडियो फुटेज व फोटोज पोस्ट की जा रही हैं।

रक्षा तैयारियों को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसके तहत भारतीय सेना की अग्रिम क्षेत्रों में मौजूदगी बढ़ाई गई है, जबकि भारतीय वायुसेना आधुनिक लड़ाकू विमानों, परिवहन विमान और हेलिकॉप्टरों के माध्यम से सीमा क्षेत्रों में आवश्यक सहायता उपलब्ध करा रही है। वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए बहु-स्तरीय एयर डिफेंस प्रणाली भी तैनात की गई है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और सेना की इंजीनियर इकाइयों द्वारा एलएसी के निकट रणनीतिक सड़कों और दोहरे उपयोग (सैन्य एवं नागरिक) वाले बुनियादी ढांचे का तेजी से निर्माण किया जा रहा है। इससे दुर्गम इलाकों तक पहुंच आसान हुई है और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य बलों की शीघ्र आवाजाही संभव हो सकी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद जिन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की कमी लंबे समय तक चुनौती बनी रही, वहां अब स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हालांकि, सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी प्रस्तावित सड़क, पुल और संचार परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना अभी भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य प्रतिक्रिया और अधिक प्रभावी हो सके।

भारत लगातार यह स्पष्ट करता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। वहीं चीन समय-समय पर इस क्षेत्र पर दावा जताता रहा है, जिसे भारत सिरे से खारिज करता है। मौजूदा परिस्थितियों में सीमा क्षेत्रों में सैन्य तैयारियों के साथ-साथ आधारभूत ढांचे का विस्तार राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

एआई के कारण बिजली और पानी की खपत हो सकती है दोगुनी: यूएन

कैलिफोर्निया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) विशेषज्ञों का कहना है कि एआई मॉडल को संचालित करने वाले विशाल डेटा सेंटरों को ठंडा रखने के लिए बड़ी मात्रा में पानी और बिजली की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र ने भी एआई कंपनियों से बिजली, पानी और भूमि के उपयोग का विस्तृत विवरण मांगा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेष के अनुसार, यदि एआई का विस्तार इसी गति से जारी रहा तो आने वाले चार वर्षों में इससे जुड़ी बिजली और पानी की खपत लगभग दोगुनी हो सकती है। एआई आधारित सेवाओं जैसे चैटबॉट या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूछे गए प्रत्येक प्रश्न के पीछे हजारों उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर सर्वर काम करते हैं। इन सर्वरों के लगातार सक्रिय रहने से अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, जिसे नियंत्रित करने के लिए विशेष कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है।

अब बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलेंगी 12फीसदी से ज्यादा अल्कोहल की ओरल दवा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 12फीसदी से ज्यादा एथिल अल्कोहल वाली ओरल दवाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इन दवाओं को लेकर नियम और सख्त किए हैं। अब 30 मिलीलीटर से बड़ी पैकिंग में बिकने वाली 12फीसदी से ज्यादा एथिल अल्कोहल वाली ओरल दवाएं शेड्यूल एच1 में शामिल होंगी। सरकार का आदेश है कि इन दवाओं की बिक्री अब डॉक्टर के पर्चे पर ही होगी, साथ ही इनका रिकॉर्ड रखना भी जरूरी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह नई अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन के 6 महीने बाद लागू होगी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस नियम के लागू होने का मतलब है कि ऐसी दवाएं अब बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं बेची जा सकेंगी, साथ ही इन दवाओं की बिक्री का रिकॉर्ड भी रखना होगा, जैसा शेड्यूल एच1 की दवाओं के लिए जरूरी होता है। शेड्यूल एच1 ऐसी दवाओं की सूची है जिनकी बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। इन दवाओं को केवल पंजीकृत डॉक्टर के पर्चे पर ही खरीदा जा सकता है। मेडिकल स्टोर को इनकी बिक्री का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखना होता है।

सरकार ने इस बारे में बताया है कि ज्यादा अल्कोहल वाली कुछ ओरल दवाओं के गलत इस्तेमाल की आशंका रहती है। खासतौर पर इन दवाओं को नशे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नए नियम से ऐसी दवाओं की बिक्री पर अब निगरानी बढ़ेगी। इससे दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होने के 6 महीने बाद लागू होगा यानि यह अगले साल जनवरी से मान्य होगा। बता दें यह बदलाव केवल 30 मिलीलीटर से बड़ी पैकिंग में बिकने वाली और 12फीसदी से ज्यादा एथिल अल्कोहल वाली ओरल दवाओं पर लागू होगा। सरकार ने इस प्रस्ताव पर पहले लोगों से सुझाव मांगे थे, लेकिन कोई आपत्ति या सुझाव नहीं मिलने के बाद इसे अंतिम रूप दे दिया गया। अल्कोहल सिर्फ ऐलोपैथी ही नहीं बल्कि होम्योपैथी की दवाओं में भी इस्तेमाल होती है।

मिस्त्र के रेगिस्तान में मिला 1700 साल पुराना खजाना

18 प्राचीन मकबरों के साथ मिले सोने की जीभ वाले कंकाल

इजिप्ट। मिस्त्र के पश्चिमी रेगिस्तान में पुरातत्वविदों के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी है। दखला ओएसिस में खुदाई के दौरान चौथी सदी के एक पूरे बीजान्टिन शहर को खोज निकाला गया है, जो अपने आप में कई प्राचीन रहस्य समेटे हुए है। इस खोज के दौरान रिहायशी इमारतों के साथ-साथ एक प्राचीन चर्च, सोने के सिक्के और पुराने बर्तन भी बरामद हुए हैं। यह पूरा प्राचीन शहर उस दौर का है जब मिस्त्र बीजान्टिन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इसके साथ ही अलेक्जेंड्रिया के पास मरीना अल-अलमीन में हुई खुदाई में 18 ऐसे खौफनाक और हैरान करने वाले मकबरे मिले हैं, जिनमें कंकालों के मुंह से सोने की जीभ मिली है। वहां के पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय ने इस असाधारण खोज को इतिहास की एक बड़ी सफलता बताया है।

पुरातत्वविदों के अनुसार, रेगिस्तान के नीचे दबे इस पुराने शहर में व्यवस्थित सड़कें बनी हुई थीं, जो आपस में मिलकर बड़े चौक और सार्वजनिक स्थल बनाती थीं। यह ऐतिहासिक स्थल न्यू वैली प्रांत में स्थित है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने के बेहद करीब है। शहर के मुख्य हिस्से में चौथी सदी के मध्य का एक बड़ा चर्च और सुरक्षा के लिए बने दो ऊंचे वॉचटावर मिले हैं। यहाँ मोटी दीवारों वाले मजबूत घर मिले हैं, जिनमें बड़े रिसेप्शन हॉल और गुंबददार छतें बनी हुई थीं। इनमें से एक घर चर्च के डीकन टीसस का था, जिसे शुरूआती दौर में चर्च की तरह ही इस्तेमाल किया जाता था। खुदाई में यहां प्राचीन ओवन, रसोई घर और रोमन सम्राट कांस्टेंशियस द्वितीय (शासनकाल 337 से 361 ईस्वी) के समय के सोने के सिक्के मिले हैं। साथ ही मिट्टी के करीब 200 ऐसे टुकड़े मिले हैं, जिनका उपयोग उस दौर में व्यावसायिक लेन-देन के हिसाब-किताब के लिए किया जाता था। दूसरी तरफ, अलेक्जेंड्रिया शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर मरीना अल-अलमीन साइट पर खोजे गए 18 मकबरों में से 11 चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, जो लगभग आठ मीटर गहरे हैं।

घर में मिला सोना, आयकर विभाग कब करता है जब्त?

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश विजिलेंस विभाग द्वारा आगरा में तैनात रहे पूर्व असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ललित कुमार के लखनऊ स्थित आवास से 1.62 करोड़ रुपये नकद, 13 किलोग्राम सोना, 9 किलोग्राम चांदी और लगभग 35 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिलने के बाद, आम जनता के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर किसी के घर से इतनी बड़ी मात्रा में सोना, चांदी या नकदी मिलती है तो कानून उसके साथ क्या करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सिर्फ ज्यादा सोना या चांदी होना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। असली सवाल यह होता है कि क्या उस संपत्ति का वैध स्त्रोत साबित किया जा सकता है। यदि व्यक्ति खरीद का बिल, आय का वैध स्त्रोत, बैंक रिकॉर्ड, वसीयत या उपहार से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत कर पाता है, तो आमतौर पर किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि, यदि संपत्ति का कोई हिसाब नहीं मिलता, तो मामला गंभीर हो जाता है और आयकर विभाग सख्त कार्रवाई कर सकता है।

यदि आयकर विभाग की तलाशी या छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में सोना, चांदी या नकदी मिलती है और उसका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड या वैध स्त्रोत नहीं होता, तो अधिकारी उसे जब्त कर सकते हैं। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी कर यह साबित करने का मौका दिया जाता है कि यह संपत्ति किस आय से खरीदी गई या उसे कैसे हासिल किया गया। यदि व्यक्ति संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है, तो इसे अघोषित आय या अघोषित संपत्ति माना जा सकता है। ऐसे मामलों में अघोषित आय पर 60 प्रतिशत की दर से भारी टैक्स लगाया जाता है। इस टैक्स के साथ 25 प्रतिशत सरचार्ज और 4 प्रतिशत सेस भी जुड़ता है, जिससे कुल टैक्स देनदारी लगभग 78 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। इसके अलावा,

विभाग 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त पेनल्टी भी लगा सकता है, जिसका अर्थ है कि कई मामलों में सोने या चांदी की कुल कीमत का लगभग 88 प्रतिशत हिस्सा टैक्स और जुमार्ने के रूप में वसूला जा सकता है। अगर मामला भ्रष्टाचार, हवाला, तस्करी या किसी अन्य गंभीर अपराध से जुड़ा पाया जाता है, तो सिर्फ टैक्स ही नहीं, बल्कि आपराधिक कार्रवाई और जेल तक की नौबत आ सकती है।हालांकि, यह भी समझना जरूरी है कि घर में रखा हर सोना जब्त नहीं होता। सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की गाइडलाइंस के अनुसार, परिवार में सामान्य इस्तेमाल के गहनों को लेकर कुछ राहत दी गई है।

जांच के दौरान, विवाहित महिला के पास 500 ग्राम तक, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम तक और परिवार के प्रत्येक पुरुष सदस्य के पास 100 ग्राम तक सोने के आभूषणों को सामान्य परिस्थितियों में जब्त नहीं किया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन पर कभी सवाल नहीं उठ सकता, यदि आयकर विभाग को आय के स्त्रोत पर संदेह होता है, तो बाद में इनकी भी जांच की जा सकती है। सोने के बिस्किट, सिक्के या बुलियन के मामले में यह छूट लागू नहीं होती। यदि तलाशी के दौरान ऐसे वस्तुएं मिलती हैं, तो उनके लिए खरीद का बिल या वैध स्त्रोत बताना अनिवार्य होता है।

ऐसा न करने पर विभाग उन्हें अघोषित संपत्ति मानकर कार्रवाई कर सकता है। चांदी के मामले में सोने की तरह कोई तय ग्राम सीमा निर्धारित नहीं है। इसलिए, यदि बड़ी मात्रा में चांदी मिलती है, तो उसके स्त्रोत का पूरा हिसाब देना पड़ सकता है। वैध दस्तावेज नहीं होने पर विभाग उसे भी अघोषित संपत्ति मानकर टैक्स और अन्य कार्रवाई कर सकता है। संक्षेप में, कानून की नजर में सबसे अहम बात यह नहीं है कि घर में कितना सोना या चांदी है, बल्कि यह है कि उसका स्त्रोत कितना पारदर्शी और वैध है। संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड होने पर आमतौर पर कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन बिना हिसाब वाली संपत्ति मिलने पर भारी टैक्स, पेनल्टी और गंभीर मामलों में आपराधिक कार्रवाई तक हो सकती है।

छग को रेल विकास के लिए 175 करोड़, सीएम ने पीएम-रेलमंत्री का जताया आभार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए अतिरिक्त होमिंग सुविधाओं के निर्माण हेतु ?175 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति प्रदान किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में रेलवे अधोसंरचना अभूतपूर्व गति से सशक्त हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत यह परियोजना राज्य के रेल नेटवर्क को और अधिक सक्षम एवं आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से रायपुर में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के रखरखाव की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथ ही माल एवं यात्री परिवहन की दक्षता बढ़ेगी और रेलवे परिचालन को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। इससे भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप रेलवे अधोसंरचना को भी मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि यह परियोजना छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख रेल, औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण को नई गति प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक राज्यों में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। ऐसे में रेलवे अधोसंरचना का विस्तार औद्योगिक विकास, व्यापार और निवेश को नई गति देगा।

उन्होंने कहा कि रायपुर में विकसित होने वाली यह नई सुविधा राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत रेल, औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वित प्रयासों का ही परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में लगातार नई विकास परियोजनाओं को स्वीकृति मिल रही है। रेलवे नेटवर्क का विस्तार, आधुनिक सुविधाओं का विकास और नई अधोसंरचना तैयार होने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्वास व्यक्त किया कि यह परियोजना विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के विकास, निवेश को बढ़ावा देने और बेहतर परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में रेलवे क्षेत्र में होने वाले ऐसे निवेश प्रदेश के समग्र विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने

पुलिस की जनरल परेड बलवा ड्रिल अभ्यास भी

रायपुर। पुलिस लाईन में आयोजित जनरल परेड की एसीपी अमित तुकाराम काम्बले, भापुसे ने परेड की सलामी ली गई। सलामी पश्चात् अधिकारी कर्मचारियों के वेशभूषा एमटी शाखा के वाहनों का निरीक्षण किया। तत्पश्चात् मार्च पास्ट के उपरांत बलवा ड्रील का अभ्यास कराया गया। बलवा ड्रिल के नेतृत्व नीलेश कुमार द्विवेदी एसीपी ने किया।

बलवा ड्रील पार्टियों में अश्रु गैस दल, केन, लाठी एवं रायफल पार्टी सहित कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए विभिन्न तकनीकों प्रदर्शन किया । प्रदर्शन के दौरान अतिरिक्त डीसीपी यातायात डी0आर0 पोर्ते, एसीपी यातायात रमेश येरेवार एवं रक्षित निरीक्षक श्री अनीष सारथी सम्मिलित थे। इस बलवा ड्रिल अभ्यास एवं साप्ताहिक परेड में 595 अधिकारी, कर्मचारी सम्मिलित हुए।

ताजा खबर
संक्षिप्त

अनुसंधान और नवाचार को बताया किसानों की समृद्धि की कुंजी

रायपुर। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का दौरा कर विश्वविद्यालय की शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों का जायजा लिया। इस दौरान संचालक कृषि राहुल देव भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अनुसंधान प्रयोगशालाओं, कृषि अनुसंधान परियोजनाओं, इन्क्यूबेशन सुविधाओं और विभिन्न अधोसंरचनाओं का निरीक्षण किया। विश्वविद्यालय द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और कृषि विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि विश्वविद्यालय के विकास के लिए हरसंभव मदद करेगी। कृषि उत्पादन आयुक्त ने विश्वविद्यालय के अनुसंधान प्रक्षेत्र में औषधीय एवं सगंध फसलों का अवलोकन किया। टिश्यू कल्चर लैब में केला, गन्ना और बांस के ऊतक संवर्धित पौधों के उत्पादन की जानकारी ली। उन्होंने कृषि संग्रहालय, विश्वविद्यालय के उत्पादों के विक्रय केंद्र और भारत सरकार द्वारा स्थापित आधुनिक मौसम वेधशाला का भी निरीक्षण किया। डॉ. आर.एल. रिछारिया जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला और बायोटेक पार्क के भ्रमण के दौरान उन्हें देश के सबसे बड़े और विश्व के दूसरे सबसे बड़े धान जर्मप्लाज्म संग्रह के बारे में जानकारी दी। कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने बताया कि यहां धान की 23,250 पारंपरिक किस्मों के जनन द्रव्य संरक्षित हैं, जिनमें कई औषधीय और पोषक गुणों से भरपूर हैं। इनके आधार पर नई उन्नत धान किस्मों का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य फसलों की छह हजार से अधिक किस्मों का भी संरक्षण किया गया है।

अबूझमाड़ तक पहुंची विकास, सड़क ने बदल दी ग्रामीणों की जिंदगी

रायपुर। कभी घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे अबूझमाड़ के कटेर गांव तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था। बारिश के दिनों में संकरी पगडंडियां भी कीचड़ में बदल जाती थीं। बीमारों को अस्पताल पहुंचाने, बच्चों को स्कूल भेजने और किसानों को अपनी उपज बाजार तक ले जाने में घंटों लग जाते थे। आज वही गांव पक्की सड़क से जुड़ चुका है और इसके साथ ही ग्रामीणों की जिंदगी भी बदलने लगी है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत डोंडरीबेड़ा कैंप से कटेर तक 8.75 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण लगभग 8.56 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। यह सड़क केवल दो स्थानों को नहीं जोड़ती, बल्कि अबूझमाड़ के दूरस्थ जनजातीय अंचल को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का माध्यम बन गई है। सड़क बनने के बाद अब एम्बुलेंस, शासकीय वाहन और अन्य जरूरी सेवाएं सीधे गांव तक पहुंच रही हैं।

जल जीवन मिशन 2.0 - गांवों में भी लगेंगे वाटर मीटर

हर घर शुद्ध जल के लिए पंचायतों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी, होगा सोशल ऑडिट

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण पेयजल योजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता और सुचारू संचालन को लेकर आज मंत्रालय (महानदी भवन) में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने आज एक बैठक में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत पीएच?ई विभाग और छत्तीसगढ़ जल जीवन मिशन के अधिकारियों के साथ संचालन एवं रखरखाव नीति पर व्यापक चर्चा की। और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

पंचायतों को हस्तांतरित होगी व्यवस्था

बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि राज्य में निर्मित सभी नल-जल योजनाओं का सफल संचालन शासन के निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाए। पेयजल योजनाओं की संस्थागत व्यवस्था को पूरी तरह से ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाएगा। जिसके लिए पंचायतों को हर आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। इन योजनाओं का रखरखाव ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के माध्यम से होगा, जिससे जन-सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। योजनाओं का सही संचालन और गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति जांचने के लिए सोशल ऑडिट (सामाजिक अंकेक्षण) कराया जाए। इसके साथ ही, प्रत्येक गाँव की ग्राम सभा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति के मुद्दे पर अनिवार्य रूप से चर्चा सुनिश्चित की जाए।

बैठक के दौरान योजनाओं के रखरखाव के लिए बजट प्रबंधन और उचित जल शुल्क निर्धारण पर चर्चा हुई। जल की बर्बादी (क्षति) को कम करने और बेहतर राजस्व प्राप्ति के लिए भविष्य में बजट प्रावधानों के अनुसार वाटर मीटर लगाने पर भी विचार-विमर्श किया गया। पेयजल की गुणवत्ता का मूल्यांकन, विभिन्न स्तरों पर मॉनिटरिंग व्यवस्था, अनुपालन और सामुदायिक भागीदारी लेखा परीक्षा को लेकर अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी दी। बैठक में विभागीय सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ नीति के प्रारूप और उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से प्रस्तुतिकरण दिया। इस उच्च स्तरीय बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह सहित जल जीवन मिशन, पीएचई और अन्य संबद्ध विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बीजेपी संयुक्त प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यसमिति बैठक : 2028 चुनाव की बनी रणनीति

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज पार्टी के सभी 17 प्रकोष्ठों की संयुक्त प्रदेश कार्यसमिति की बैठक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की अध्यक्षता में हुई। करीब ढाई घंटे तक चली इस बैठक में आगामी रणनीति, सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने को लेकर मंथन किया गया। साथ ही वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रकोष्ठों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन महामंत्री पवन साय सहित सभी 17 प्रकोष्ठों के प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को दिए चार मंत्र

बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिर पर बर्फ रखो, यानी दिमाग हमेशा ठंडा रखो। मुंह में मिश्री रखो, यानी जुबान हमेशा मीठी रखो। पैर में चक्र रखो यानी पार्टी के काम के लिए हमेशा चलायमान रहो।

पार्टी के प्रति अगाध श्रद्धा रखो, ताकि आपस में भाईचारा बना रहे। बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि इससे पहले मोर्चा और प्रकोष्ठों की बैठक हुई थी। आज सभी प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता और अध्यक्ष इस बैठक में शामिल रहे। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं से यह भी कहा गया कि वे जनता से अधिक से अधिक जनसंपर्क करें।

प्रधानमंत्री की गारंटी और मुख्यमंत्री के सुशासन से तेज गति से हो रहा विकास : उप मुख्यमंत्री साव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन के कारण छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में तेज गति से विकास हो रहा है। उन्होंने बेमेतरा जिले के नगर पंचायत भिंभौरी में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने जनता से किए हर वादे को पूरा किया है। उन्होंने कार्यक्रम में 465.84 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहे नवीन महाविद्यालय भवन एवं 14.28 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहे किसान सामुदायिक भवन का भूमिपूजन कर नगर पंचायत भिंभौरी को बड़ी सौगातें दी। सांसद श्री विजय बघेल, विधायक श्री दीपेश साहू और श्री ईश्वर साहू भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नवीन नगर पंचायत भिंभौरी में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने यहां घर-घर में नल से जल पहुंचाने के लिए जल आवर्धन योजना के लिए 4 करोड़ रुपए एवं विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री और चेक भी वितरित किए गए।

नवंबर-दिसंबर में होंगे 17 निकायों में चुनाव-साव

रायपुर। डिप्टी सीएम अरुण साव ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश के 17 निकायों में नवंबर-दिसंबर में चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में भी भाजपा को जीत हासिल होगी। साव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि बस्तर में नक्सलवाद के सफाए के सौ दिन पूरे होने पर कहा कि डबल इंजन सरकार ने वह कार्य कर दिखाया है, जिसे लंबे समय तक असंभव माना जाता था। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की प्रभावी रणनीति का परिणाम है। अरुण साव ने कहा कि वर्षों तक नक्सलवाद के कारण बस्तर विकास की दौड़ में पीछे रह गया था। अब सरकार का लक्ष्य बस्तर को विकास की मुख्यधारा से जोडना है। इसके लिए सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने बताया कि उन्होंने हाल ही में बस्तर संभाग के पांच जिलों का दौरा कर सडक़, पेयजल, पुल-पुलिया तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है, ताकि लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आए और विकास को नई गति मिले।

नगरीय निकाय चुनावों के संबंध में अरुण साव ने कहा कि दिसंबर-जनवरी में चुनाव प्रस्तावित हैं और राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और वर्षभर जनता के बीच रहकर काम करती है।

उन्होंने दावा किया कि पिछले ढाई वर्षों में राज्य सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी नगरीय निकायों में विकास कार्य कराए हैं। इसी विकास और जनता के विश्वास के आधार पर आगामी 17 नगरीय निकायों के चुनावों में भी भाजपा को व्यापक जनसमर्थन मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में शहरों का विकास प्रभावित हुआ, जबकि वर्तमान सरकार ने शहरों के सुव्यवस्थित और संतुलित विकास को प्राथमिकता दी है।

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू

मुख्य सचिव ने ली उच्च स्तरीय बैठक, अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारियां

रायपुर। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गरिमापूर्वक मनाया जाएगा। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन सुबह 9 बजे से होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर शानदार परेड का आयोजन होगा। समारोह स्थल पर परेड कार्यक्रम में भाग लेने वाली टुकड़ियों के निर्धारण एवं रिहर्सल के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल द्वारा पुलिस महानिदेशक के मार्ग दर्शन में सभी आवश्यक तैयारियां एवं व्यवस्था की जाएगी। साथ ही यातायात, पार्किंग,ट्रैफिक एवं सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस महानिरीक्षक रायपुर द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई की व्यवस्था तथा मंच, पंडाल व्यवस्था और बैठक व्यवस्था का निर्धारण आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के द्वारा की जाएगी। स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों का निर्धारण स्कूल शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग द्वारा किया जाएगा। स्कूली बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के रिहर्सल कार्यक्रम में सभी व्यवस्थाओं कलेक्टर रायपुर द्वारा की जायेंगी। इसी तरह से स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबंध में अन्य विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजित किए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के निर्धारण के संबंध में शीघ्र ही निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर 7 से 15 अगस्त तक सभी शासकीय कार्यक्रमों में वंदे मातरम् का गायन किया जाएगा। इसके लिए संस्कृति विभाग दिशा-निर्देश जारी करेगा।

तीर से हमले में गंभीर घायल का अम्बेडकर में सफल ऑपरेशन

रायपुर। मेकाहारा रायपुर के जनरल सर्जरी विभाग ने तीर से गंभीर रूप से घायल मरीज के जीवन बचाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। विभागाध्यक्ष डॉ. मंजु सिंह केस के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि - गरियाबंद जिले के निवासी एक मरीज को पीठ से होते हुए पेट में तीर लगने के कारण गंभीर अवस्था में उच्च स्तरीय उपचार के लिए अम्बेडकर अस्पताल रेफर किया गया था। प्रारंभिक चिकित्सकीय परीक्षण एवं आवश्यक जांचों में पाया गया कि तीर पेट में गहराई तक धंसा हुआ था, जिससे पेट के भीतर के महत्वपूर्ण अंग गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। इसके कारण एब्डोमेन में परफोरेशन, आंतरिक रक्तस्राव तथा संक्रमण का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था। मरीज के अस्पताल पहुंचते ही विशेषज्ञ निगरानी में 2 जुलाई को सर्जरी विभाग की टीम ने इस जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया।

ऑपरेशन के दौरान अत्यंत सावधानी पूर्वक तीर को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया। इसके पश्चात क्षतिग्रस्त आंतरिक ऊतकों एवं अंगों की मरम्मत की गई, रक्तस्राव को नियंत्रित किया गया तथा पेट के भीतर जमा रक्त एवं दूषित द्रव को साफ कर आवश्यक जीवनरक्षक प्रक्रियाएं की गईं।

महत्वपूर्ण ख़बर

शॉर्ट पिच गेंदें बनी वैभव की कमजोरी

■ लंदन। 15 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर सुर्खियां बटोरने वाले उभरते हुए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अब तक इंग्लैंड दौरे में प्रभावित नहीं कर पाये हैं। वैभव ने अब तक इस दौरे में तीन टी20 मैच खेले हैं। जिसमें वह 14, 13 और 15 रन बना पाये हैं। इस प्रकार वह तीन मैचों में कुल 42 रन ही बना पाये हैं। इन तीनों ही मैचों में वैभव ने उतरते ही बड़े शॉट लगाये पर वह विकेट पर टिक कर बड़ी पारी नहीं खेल पाये। इससे उनके शॉट चयन पर भी सवाल उठने लगे हैं। वैभव ने इससे पहले आईपीएल में जबरदस्त प्रदर्शन किय था लेकर इंग्लैंड की उछाल भरी तेज पिचों पर वह हालात के अनुसार खेलने में विफल रहे हैं।

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर आफताब बलोच के रनों से जुड़ा अद्भुत संयोग

लाहौर। क्रिकेट इतिहास में कई हैरान करने वाली घटनाएं भी समय-समय पर होती रही हैं। ऐसी ही एक अविश्वसनीय कहानी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर आफताब बलोच से जुड़ी है। इस क्रिकेटर ने सला 1973 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 428 रनों का एक विशाल स्कोर बनाया था पर उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक साल बाद किस्मत ने उनके साथ एक ऐसा अनोखा खेल खेला जिसे जानकार सभी हैरान हो गये। ये था उन्हें जो कमरा मिला था उसका नंबर उनके बनाये रनों के बराबर था। जिससे सभी हैरान हो गये।

साल 1973 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर से खेलते हुए आफताब बलोच ने बलूचिस्तान के खिलाफ कराची के मैदान पर यह ऐतिहासिक कारनामा किया। उन्होंने 10 घंटे से अधिक समय तक बल्लेबाजी करते हुए 25 चौकों की मदद से 428 रनों की लंबे पारी खेली। यह प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास का सातवां सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। उनकी यह पारी न केवल रनों के विशाल अंबार के लिए, बल्कि पिच पर टिके रहने की उनकी अद्भुत क्षमता के लिए भी जानी जाती है। क्रिकेट के पूरे इतिहास में उनसे अधिक समय तक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी केवल छह ही रहे हैं। इस पारी ने

उन्हें रातों-रात क्रिकेट जगत में एक सितारा बना दिया।

सबसे हैरानी की बात ये है कि आफताब अपने पूरे करियर में पाक के लिए केवल दो टेस्ट मैच ही खेल पाए। इसका मुख्य कारण उस समय पाकिस्तानी टीम का बेहद मजबूत बल्लेबाजी क्रम था। सादिक मोहम्मद, माजिद खान, जहीर अब्बास, आसिफ इकबाल और मुश्ताक मोहम्मद जैसे विश्व-प्रसिद्ध और अनुभवी बल्लेबाजों की मौजूदगी में बलोच जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी को भी राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए संघर्ष करना पड़ा।

हालांकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक मौके नहीं मिले, लेकिन उनके करियर से जुड़ा एक जादुई किस्सा हमेशा याद रखा जाएगा। साल 1974 में जब पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड दौरे पर थी और बलोच भी उस टीम का हिस्सा थे। हालांकि इस दौरे पर उन्हें एक भी टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब वे इंग्लैंड पहुंचे, तो होटल प्रशासन ने उन्हें ठहरने के लिए जो कमरा अलॉट किया, उसका नंबर 428 था। यह वही संख्या थी जो उन्होंने एक साल पहले कराची के मैदान पर अपनी ऐतिहासिक पारी में रनों के रूप में बनाई थी। यह संयोग इतना सटीक और अविश्वसनीय था कि इसे महज इत्तेफाक कहना मुश्किल है, मानो किस्मत खुद उनके उस महान रिकॉर्ड को सलाम कर रही हो। आफताब बका अंतरराष्ट्रीय करियर भले ही लंबा न रहा हो, लेकिन प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनके 428 रन और इंग्लैंड के होटल में मिला कमरा नंबर 428, हमेशा क्रिकेट के अनोखे पलों के लिए वह हमेशा याद किये जाएंगे।

31 साल बाद विंबलडन फाइनल में पहुंचने वाले पहले जर्मन खिलाड़ी बने एलेक्जेंडर ज्वेरेव

जर्मनी के स्टार खिलाड़ी एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने विंबलडन 2026 के पहले सेमीफाइनल मैच में इतिहास रच दिया है. एलेक्जेंडर ज्वेरेव अपने 10 साल के करियर में पहली बार विंबलडन के फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं. इसी के साथ वह 31 साल बाद विंबलडन फाइनल में पहुंचने वाले पहले जर्मन पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं. साल 1995 के बाद पहली बार किसी जर्मन खिलाड़ी ने विंबलडन के फाइनल में अपनी जगह बनाई है. इससे पहले जर्मनी के बोरिस बेकर ने 31 साल पहले विंबलडन का फाइनल मैच खेला था. इतना ही नहीं बोरिस बेकर और माइकल स्टिच के बाद विंबलडन के फाइनल में पहुंचने वाले सिर्फ तीसरे जर्मन पुरुष खिलाड़ी बने हैं. एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सेमीफाइनल मैच में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को लगातार तीनों सेटों में 7-6, 6-2, 6-4 से आसानी से हराकर फाइनल में एंट्री मारी है.

एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने लगातार दूसरी बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में अपनी जगह पक्की की है. इसी साल 2026 में उन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया था. अब वह विंबलडन खिताब जीतने से सिर्फ एक कदम दूर हैं. ज्वेरेव ने सेमीफाइनल में कमाल का प्रदर्शन किया और पहले सेट के बाद तो उन्होंने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को गेम में बने ही नहीं रहने दिया. पहले सेट में फेरी ने ज्वेरेव को जरूर टक्कर दी. लेकिन, जब बात टाईब्रेक पर आई तो वह एक भी पॉइंट हासिल नहीं कर पाए. इस तरह ज्वेरेव ने पहला सेट 7-6 से अपने नाम किया. इसके बाद उन्होंने बाकी दोनों सेट 6-2, 6-4 से आसानी से जीता और फाइनल में अपनी जगह बनाई. यह मुकाबला 2 घंटे और 13 मिनट तक चला.

पहली बार विंबलडन फाइनल खेलेंगे ज्वेरेव

विंबलडन फाइनल में पहुंचने के साथ ही एलेक्जेंडर ज्वेरेव अब चारों ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाली दुनिया के चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं. बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है. जर्मनी के लिए आखिरी बार साल 1991 में माइकल स्टिच ने विंबलडन का खिताब जीता था. अब ज्वेरेव पहली बार विंबलडन का फाइनल खेलेंगे, तो उनके देश को उनसे काफी उम्मीद होगी. एलेक्जेंडर ज्वेरेव इससे पहले विंबलडन के 'राउंड ऑफ 16' से कभी आगे नहीं बढ़ पाए थे. इतना ही नहीं, इस साल 2026 में उन्होंने तीसरी बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में अपनी जगह बनाई है. इसी साल उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन के फाइनल खेले थे. इस दौरान उन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया था, जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में उन्हें हार मिली थी.

अब तक केवल चार बल्लेबाज ही लगा पाये हैं टेस्ट क्रिकेट में दो-दो तिहरे शतक

मुम्बई। टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाना बेहद मुश्किल माना जाता है। इसके लिए बल्लेबाज में केवल कौशल ही नहीं धैर्य, मानसिक मजबूती और क्रीज पर घंटों टिके रहने कला भी आनी चाहिये। वहीं अगर अपने करियर में दो-दो तिहरे शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो केवल चार खिलाड़ियों ने ही अब तक ये उपलब्धि शामिल की है। इसमें भारत के वीरेन्द्र सहवाग भी शामिल हैं। अपने करियर में दो दो तिहरे शतक लगाने की ये उपलब्धि सबसे पहले महान बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन ब्रैडमैन, ने हासिल की। इसके अलावा ये आंकड़ा वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा, किस गेल और भारत के सहवाग ने भी हासिल किया।

डॉन ब्रैडमैन : ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन ब्रैडमैन की बात करें तो उन्होंने साल 1928 से 1948 के बीच मात्र 52 टेस्ट मैच खेले। इन 52 मैचों की 80 पारियों में उन्होंने 10 बार नाबाद रहते हुए कुल 6,996 रन बनाए। उनका हैरान कर देने वाला औसत 99.94 का रहा, जिसमें 29 शतक और 13 अर्धशतक शामिल थे। ब्रैडमैन ने दो तिहरे शतक लगाये जिसमें उनका सबसे अधिक स्कोर 334 रन रहा।

वीरेंद्र सहवाग : वहीं भारत के वीरेंद्र सहवाग भी इस विशिष्ट क्लब का हिस्सा हैं, वह ये उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। आम तौर पर माना जाता था कि

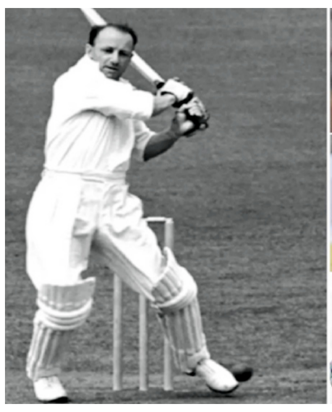

टेस्ट में तिहरा शतक बनाने के लिए रक्षात्मक खेल जरूरी है, लेकिन सहवाग ने अपनी आक्रामक शैली से इस धारणा को गलत करार दिया। साल 2001 से 2013 के बीच भारत और आईसीसी टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए सहवाग ने 104 टेस्ट मैचों की 180 पारियों में 8,586 रन बनाए। सहवाग का औसत 49.34 का रहा. उन्होंने अपने करियर में 23 शतक और 32 अर्धशतक लगा। उनके दो तिहरे शतकों में उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ स्कोर 319 रन रहा।

क्रिस गेल : वेस्टइंडीज के क्रिस गेल की पहचान टी-20 और एकदिवसीय के विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर होती है पर लाल गेंद के क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड यह साबित करता है कि वे लंबी रेस के घोड़े भी थे। वह ये रिकार्ड बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। सा 2000 से 2014 के बीच वेस्टइंडीज के लिए 103 टेस्ट खेलने वाले गेल ने 182 पारियों में बल्लेबाजी की और कुल 7,214 रन बनाये। 42.18 के औसत से रन बनाने वाले गेल ने अपने टेस्ट करियर में 15 शतक और 37 अर्धशतक लगाये और इस दौरान दो तिहरे शतक लगाये। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 333 रन रहा।

ब्रायन चार्ल्स : वेस्टइंडीज के ब्रायन चार्ल्स लारा टेस्ट में तिहरा शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज हैं। साल 1990 से 2006 के बीच लारा ने वेस्टइंडीज की ओर से कुल 131 टेस्ट मैच खेले। 232 पारियों के अपने करियर में उन्होंने 11,953 रन बनाए। लारा का टेस्ट औसत 52.88 का रहा, जिसमें 34 शतक और 48 अर्धशतक शामिल थे। लारा के नाम 375 रनों का एक रिकार्ड है। इसके अलावा वह नाबाद 400 रन बनाने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज हैं। ये चारों ये वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने खेल से क्रिकेट को नई दिशा दी।

टूटा बेल्जियम का सपना, 16 साल बाद स्पेन ने बनाई सेमीफाइनल में एंट्री, रोमांच से भरा रहा मैच

फीफा वर्ल्ड कप 2026 रोमांचक अंदाज में आगे बढ़ते हुए सेमीफाइनल की ओर बढ़ रहा है. क्वार्टरफाइनल मैच में स्पेन और बेल्जियम के बीच एक रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें आखिरी मिनट में गोल करके स्पेन ने बाजी मारी और 16 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई है.

वहीं, बेल्जियम की टीम का सपना यहीं टूट गया है. अब फाइनल मैच में स्पेन का सामना फ्रांस से होगा, जो यकीनन एक धमाकेदार मैच होने वाला है.

स्पेन ने आखिरी में जाकर मारी बाजी

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में स्पेन और बेल्जियम के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया. लॉस एंजिलिस स्टेडियम में हुए इस मैच में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से

हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. स्पेन ने 30वें मिनट में फाबियन रुइज के गोल से बढ़त बनाई, लेकिन बेल्जियम ने 41वें मिनट में चार्ल्स डी केटेलारे के गोल की बदौलत बराबरी कर ली. इसके बाद दोनों टीमों ने लगातार आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन निर्णायक पल 88वें मिनट में आया, जब मिकेल मेरिनो ने गोल दागकर स्पेन को 2-1 की बढ़त दिला दी. बेल्जियम ने अंतिम मिनटों में बराबरी की भरपूर कोशिश की, लेकिन स्पेन की मजबूत रक्षापंक्ति ने उसे सफल नहीं होने दिया. इस जीत के साथ स्पेन ने लगातार शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जहां उसका सामना फ्रांस से होगा. वहीं, बेल्जियम का टूनार्मेंट में सफर क्वार्टर फाइनल पर समाप्त हो गया।

फ्रांस के साथ खेला जाएगा फाइनल मैच

फीफा वर्ल्ड कप 2026 रोमांचक अंदाज में आगे बढ़ रहा है. सेमीफाइनल मुकाबलों में अब तक फ्रांस और स्पेन ने अपनी जगह पक्की कर ली है. क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से और स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराया है. अन्य सेमीफाइनल टीमों की तस्वीर इंग्लैंड ५२ नॉर्वे और अर्जेंटीना ५२ स्विट्जरलैंड के क्वार्टर फाइनल मैचों के बाद साफ होगी. आपको बता दें, सेमीफाइनल में स्पेन का सामना फ्रांस से होने वाला है.

ई20 ईंधन पर सरकार का जवाब: क्यों नहीं मिलेंगे शुद्ध पेट्रोल और ई10 के विकल्प? इन चुनौतियों का दिया हवाला

नई दिल्ली। उपभोक्ताओं को शुद्ध पेट्रोल, ई10 और ई20 ईंधन के बीच विकल्प क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस बारे में चिंताओं का जवाब देते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत के विशाल ईंधन वितरण नेटवर्क में कई पेट्रोल ग्रेड बनाए रखने से प्रमुख परिचालन और लॉजिस्टिकल चुनौतियां पैदा होंगी।

मंत्रालय ने क्या कहा?

मंत्रालय ने कहा कि भारत का ई20 की ओर बदलाव ऑटोमोबाइल निमार्ताओं, परीक्षण एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद एक सुनियोजित परिवर्तन का हिस्सा है। मंत्रालय ने आगे कहा कि यह निर्णय वाहन अनुकूलता, इंजन प्रदर्शन, उत्सर्जन और ईंधन दक्षता को कवर करने वाले तकनीकी मूल्यांकनों पर आधारित था। ईंधन स्टेशनों पर शुद्ध पेट्रोल, ई10 और ई20 की अलग-अलग उपलब्धता की मांग को संबोधित करते हुए, मंत्रालय ने कहा कि भारत की ईंधन वितरण प्रणाली एक साथ कई राष्ट्रव्यापी आधार ईंधन धाराओं को संचालित करने के लिए डिजाइन नहीं की गई है। मंत्रालय ने कहा, 'भारत में एक लाख से अधिक खुदरा आउटलेट संचालित होते हैं, जिन्हें रिफाइनरियों, टर्मिनलों, डिपो और पाइपलाइनों के व्यापक नेटवर्क का

समर्थन मिला है।'

प्रीमियम पेट्रोल के साथ तुलना करना सही क्यों नहीं?

मंत्रालय ने आगे कहा कि अलग-अलग पेट्रोल मिश्रणों के लिए अलग-अलग आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने से हैंडलिंग लागत बढ़ेगी, इन्वेंट्री प्रबंधन जटिल होगा और परिचालन दक्षता कम होगी। मंत्रालय ने कहा कि प्रीमियम पेट्रोल के साथ तुलना करना उचित नहीं है, क्योंकि प्रीमियम ईंधन विशेष उत्पाद हैं जो सीमित मात्रा में विशेष योजकों के साथ बेचे जाते हैं और ये अलग-अलग राष्ट्रव्यापी ईंधन आपूर्ति श्रृंखलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

क्षेत्र के अनुभव का हवाला देते हुए, मंत्रालय ने कहा कि मारुति सुजुकी ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 2.84 करोड़ वाहनों की सर्विसिंग की, जिनमें 1.5 करोड़ पुराने, गैर-ई20 प्रमाणित वाहन शामिल थे, और जंग लगना, असामान्य घिसाव या पुर्जों की क्षति जैसी ई20 से संबंधित कोई समस्या नहीं पाई गई। मंत्रालय ने आगे कहा कि हीरो मोटोकॉर्प ने भी इसी तरह के अनुभव बताए हैं। मंत्रालय ने स्वीकार किया कि कुछ वाहनों की ईंधन दक्षता में ए20 के उपयोग से 3-5 प्रतिशत की कमी आ सकती है, लेकिन कहा कि ईंधन की गुणवत्ता का आकलन करने में माइलेज केवल एक कारक है।इसमें कहा गया है कि ए20 उच्च ऑक्टेन रेटिंग, बेहतर दहन, सुगम त्वरण, स्वच्छ इंजन संचालन और कम जीवनचक्र कार्बन उत्सर्जन जैसे लाभ देगा।

पुराने वाहनों के चिंताओं पर मंत्रालय ने क्या कहा?

पुराने वाहनों के संबंध में चिंताओं पर, जिन्हें शुरू में केवल ए10-संगत के रूप में लेबल किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि उच्च इथेनॉल मिश्रणों को शुरू करने से पहले ऑटोमोबाइल निमार्ताओं से परामर्श किया गया था। उन्होंने इस बदलाव का समर्थन करना जारी रखा है। मंत्रालय ने कहा 'अगर ऑटोमोबाइल निमार्ता नतीजों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते, तो वे कभी भी उत्पाद का समर्थन नहीं करते और न ही वाहनों की वारंटी का सम्मान करते। आज लगभग हर निमार्ता सभी वाहनों (पुराने या नए) की वारंटी का सम्मान कर रहा है। इसका कारण यही है कि वे परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा थे।

ईपीएफओ ने पीएफ का पूरा सिस्टम बदल दिया

नया पोर्टल कैसे करेगा काम, आप पर इसका क्या होगा असर?

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों में ईपीएफओ ने पीएफ से जुड़े नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। अगर आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है, तो ये बदलाव सीधे आप पर असर डालेंगे। नया ईपीएफओ पोर्टल, एक राष्ट्रीय डेटाबेस, क्लेम करने का नया सिस्टम, ब्याज मिलने का बदला तरीका और नई ईपीएफ स्कीम 2026, आखिर इन सबका मतलब क्या है? क्या अब पीएफ निकालना पहले से आसान हो जाएगा? नौकरी बदलने पर क्या अब भी पुराने ईपीएफओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे? इमरजेंसी में कितने पैसे निकाल सकेंगे? और क्या अब पीएफ का ब्याज भी जल्दी मिलेगा? आइए जानते हैं।

क्या है यह राष्ट्रीय डेटाबेस?

पहले ईपीएफओ के हर क्षेत्रीय कार्यालय का अपना अलग डेटाबेस होता था। अब ईपीएफओ ने सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज (उक्क्षएर) प्रोजेक्ट के तहत अपने सभी सदस्यों का डेटा एक ही राष्ट्रीय डेटाबेस में स्थानांतरित कर दिया है। यानी अब अलग-अलग क्षेत्रीय कार्यालयों में अलग-अलग डेटाबेस रखने की व्यवस्था खत्म हो गई है। इससे किसी भी अधिकृत ईपीएफओ कार्यालय से सेवाएं मिल सकेंगी।

नए ईपीएफओ सदस्य पोर्टल पर लॉगिन करते ही एक ही जगह पर सदस्यता से जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी। इसमें पीएफ बैलेंस, क्लेम की स्थिति, पेंशन योग्य सेवा का रिकॉर्ड और अब तक मिले सभी लाभ दिखाई देंगे। पहले यह जानकारी अलग-अलग सिस्टम में बंटी हुई रहती थी। अब किसी भी पीएफ क्लेम को प्रोसेस करने से पहले उसका स्वतः सत्यापन (प्री-वैलिडेशन) होगा। अगर आवेदन में कोई कमी या गलती होगी, तो उसकी जानकारी पहले ही एसएमएस और पोर्टल के माध्यम से दे दी जाएगी। इससे क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना कम होगी और पहली बार में ही क्लेम मंजूर होने की संभावना बढ़ेगी।

पहले कई सदस्य यह नहीं जानते थे कि अलग-अलग श्रेणियों में वे कितनी राशि निकाल सकते हैं। ऐसे में तय सीमा से अधिक राशि का आवेदन करने पर क्लेम खारिज हो जाता था। अब पोर्टल पर यह भी दिखाई देगा कि किस श्रेणी में कितनी राशि निकाली जा सकती है। इससे सदस्य सही राशि के लिए आवेदन कर सकेंगे। पूरी तरह केवाईसी से जुड़े और सत्यापित पांच लाख रुपये तक के एडवांस क्लेम अब ऑटो सेटलमेंट के जरिए निपटाए जाएंगे। पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है।

अगर क्लेम की जांच के दौरान किसी अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण की जरूरत होगी, तो ईपीएफओ ऑनलाइन ही सदस्य से जानकारी मांगेगा। सदस्य भी ऑनलाइन जवाब दे सकेंगे। इससे ईपीएफओ कार्यालय के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और क्लेम का निपटारा तेजी से होगा। अब क्लेम का भुगतान केंद्रीय भुगतान प्रणाली के जरिए किया जाएगा।

इंडिगो को डीजीसीए की फटकार, खतरनाक सामान के प्रबंधन में बड़ी चूक का मामला

नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो को खतरनाक सामान के प्रबंधन से संबंधित कुछ प्रावधानों में चूक के लिए चेतावनी पत्र जारी किया है। यह जानकारी एक नियामक फाइलिंग में सामने आई है। विमानन नियामक ने यह कार्रवाई जनवरी 2026 में एक उड़ान के आगमन के बाद कार्गो के फैलाव की रिपोर्ट के बाद की है।

डीजीसीए द्वारा इंडिगो को जारी किया गया यह चेतावनी पत्र जनवरी 2026 में हुई एक घटना से संबंधित है। उस समय एक उड़ान के उतरने के बाद जमीन पर कार्गो का फैलाव देखा गया था। इसके बाद हुई ऑडिट जांच में मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और विमान (खतरनाक सामान का परिवहन) नियम, 2026 के कुछ प्रावधानों से विचलन पाया गया। हालांकि, इस घटना के विशिष्ट विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

विमानों में खतरनाक सामान के प्रबंधन और परिवहन के लिए बहुत सख्त नियम लागू हैं। इन नियमों का पालन यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। किसी भी प्रकार की चूक से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। डीजीसीए इन नियमों के अनुपालन पर कड़ी निगरानी रखता है।

महत्वपूर्ण ख़बर

राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के सहयोग से जेल विभाग की ऐतिहासिक पहल

- भोपाल। मध्यप्रदेश जेल विभाग ने बंदियों के समग्र स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। महानिदेशक जेल डॉ. वरुण कपूर के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी (आर.आर.यू.), गांधीनगर, गुजरात के सहयोग से आयोजित यह सात दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थित क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान में संचालित किया जा रहा है।

महानिदेशक जेल डॉ. कपूर ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बंदियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा जेल विभाग की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। अब तक विभाग द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक प्रभावी प्रयास किए जाते रहे हैं, वहीं मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अब वैज्ञानिक एवं संस्थागत व्यवस्था विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण बंदियों के पुनर्वास, व्यवहार सुधार तथा जेलों में सकारात्मक वातावरण निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

शासकीय आईटीआई में महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट

- भोपाल। कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा प्रदेश की बेटियों को कौशल विकास से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मध्यप्रदेश शासन ने शैक्षणिक सत्र 2026 से प्रदेश के सभी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश लेने वाली महिला प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था प्रदेश के सभी शासकीय आईटीआई में लागू होगी।

5,017 करोड़ से बनेगा 98.73 किमी लंबा ग्रीनफील्ड कॉरीडोर

मालवा की समृद्धि का नया द्वार बनेगा उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन कॉरीडोर: मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मालवा अपनी बोली की मिठास और उद्यमशीलता के लिए जाना जाता है। यह कर्मयोगियों और उद्यमियों की भूमि है। हम मालवा के विकास के लिए हर जरूरी प्रबंध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड कॉरीडोर प्रोजेक्ट क्षेत्रीय विकास, समृद्धि और विश्वास का नया मार्ग है। इससे उज्जैन, जावरा और आसपास के क्षेत्रों के बीच आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह कॉरीडोर केवल उज्जैन और रतलाम के लिए विकास का हाइवे नहीं, यह पूरे मालवा क्षेत्र के समग्र विकास और अर्थव्यवस्था का नया स्पीड ट्रैक बनेगा। इस कॉरीडोर से यात्री परिवहन सुगम होगा, यात्रा समय में कमी एवं भाड़ा लागत न्यूनतम हो जाने से लॉजिस्टिक्स को भी उल्लेखनीय गति मिलेगी, जिसका लाभ उद्योग, व्यापार, कृषि और पर्यटन सभी क्षेत्रों को प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को नागदा में उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन कॉरीडोर परियोजना के भूमि पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नागदा में अस्थायी भवन में केंद्रीय विद्यालय के संचालन और सड़क सुरक्षा के जन-भागीदारी मॉडल के रूप में 'जन सेवा प्रहरी अभियान' का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन जिले में संचालित शासकीय योजनाओं के चयनित पात्र हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ-2028 की तैयारियों में यह कॉरीडोर एक महत्वपूर्ण परियोजना है। देश-विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और

उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन कॉरीडोर प्रोजेक्ट का भूमि पूजन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्रीन फील्ड फोरलेन मार्ग से उज्जैन को दिल्लीझमुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा और तेज संपर्क मिलेगा। साथ ही यह परियोजना क्षेत्र के औद्योगिक, व्यापारिक और कृषि विकास को नई गति प्रदान करेगी। लगभग 5,017 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 98.73 किलोमीटर लंबा यह कॉरीडोर मध्यप्रदेश की सड़क अधोसंरचना को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। साथ ही प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का नया आधार भी बनेगा। इससे उज्जैन जिले के 50 गांव और रतलाम जिले के 12 गांव लाभान्वित होंगे। इस कॉरीडोर से उज्जैन, घट्टिया, नागदा-खाचरौद, आलोट और जावरा के विकास को गति मिलेगी। साथ ही क्षेत्र के करीब 35 लाख नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। इस कॉरीडोर में 7 फ्लाई ओवर, 3 रेल ओवरब्रिज, 8 बड़े पुल, 22 मध्यम पुल, 36 अंडरपास, 2 ओवरपास तथा 430 पुलियाओं का निर्माण किया जाएगा।

सुविधाजनक यात्रा के लिये बेहतर अधोसंरचना प्रबंधन करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह कॉरीडोर सिंहस्थ : 2028 से पहले (दिसम्बर 2027 तक) बनकर तैयार हो जाएगा।

प्रमुख घोषणाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर उज्जैन-जावरा के मध्य वर्तमान सड़क मार्ग के चौड़ीकरण कार्य को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि नागदा और खाचरौद अब फोरलेन रोड से रतलाम शहर से कनेक्ट किया जाएगा। उन्होंने खाचरौद में नवीन मटर मंडी के लिए अतिरिक्त शासकीय भूमि देने और यहां एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नागदा विधानसभा क्षेत्र में अटलावदा-निनावटखेड़ा चंबल नदी पर नया बांध बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नागदा में नया आईटीआई केन्द्र खोलने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक और विश्वस्तरीय अधोसंरचनात्मक के निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बेहतर सड़क नेटवर्क से निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्राप्त होगी। उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन प्रोजेक्ट न केवल सिंहस्थ-2028 की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेगी, बल्कि भविष्य में मालवा अंचल के विकास और प्रदेश की प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार भी सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि यह कॉरीडोर क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखेगा। करीब 100 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से यातायात की सुगमता के साथ औद्योगीकरण को भी नई रफ्तार मिलेगी। उज्जैन-जावरा ग्रीन फील्ड कॉरिडोर पहले एक्सेस कंट्रोल्ड था, जिसे नॉन एक्सेस कंट्रोल किया गया है। उन्होंने कहा कि उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के आयोजन के लिए यह मार्ग सोने पर सुहागा जैसा होगा। विश्व स्तरीय सिंहस्थ मेले के दौरान राजस्थान, गुजरात और देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन प्रोजेक्ट अत्यंत सुगम और सुविधाजनक साबित होगा। उज्जैन क्षेत्र बदल रहा है। अब यहां साढ़े 8 करोड़ श्रद्धालु एक वर्ष में आ रहे हैं। राज्य सरकार ने 2 मेट्रोपोलिटन एरिया - इंदौर-उज्जैन-रतलाम और भोपाल-सीहोर-नर्मदापुरम घोषित कर इसमें डेवलपमेंट के काम भी शुरू कर दिए हैं। इसके बाद जबलपुर और ग्वालियर मेट्रोपोलिटन रीजन बनाने का काम प्रारंभ किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य भी बना है। मालवांचल के पीथमपुर और विक्रम उद्योगपुरी में विश्व के बड़े कारोबारी अपने उद्योग स्थापित करने के लिए आ रहे हैं। विकास की रफ्तार में अब चंबल अंचल भी पीछे नहीं है। मध्यप्रदेश की धरती पर देशभर में सबसे अधिक सीमेंट प्लांट स्थापित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा निर्धारित की गई ऋअठ (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) सहित हर वर्ग के कल्याण और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। राज्य सरकार ने ऋअठ में 2 और श्रेणियां शामिल की हैं- औद्योगिकीकरण और अधोसंरचनात्मक विकास। इसके सुखद परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस 2025) में 30 लाख करोड़ का अभूतपूर्व निवेश प्राप्त हुआ, जिसमें से अब तक 10 लाख करोड़ निवेश जमीन पर उतर चुका है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। किसान फसल लगाएं, सरकार समुचित दाम दिलवाएगी। मालवांचल में मटर की प्रोसेसिंग यूनिट और उज्जैन में पेप्सिको के फूड इंडस्ट्री पार्क का भूमि पूजन किया गया है। प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों को मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों के समान भाव बहुत जल्द उज्जैन में पेप्सिको के जरिए मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने कोई नया कर (टैक्स) नहीं बढ़ाते हुए भी 4.38 लाख करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। हमने लाड़ली बहनों के लिए प्रतिमाह 1500 रुपए का प्रावधान किया है। रक्षाबंधन से पहले जल्द ही बहनों को जुलाई माह की राशि भी मिलेगी। राज्य सरकार ने अब तक लाड़ली बहनों को 60 हजार करोड़ रूपए से अधिक की आर्थिक सहायता दी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नागदा में डेढ़ साल पहले की गई इस सड़क निर्माण घोषणा को पूरा करते हुए आज इसका भूमि पूजन किया है। यह परियोजना दिसंबर 2027 तक पूरी होगी और इसका भव्य लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंदौर-पीथमपुर ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरीडोर से भी क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी। इस कॉरीडोर से किसानों, व्यापारियों और आम लोगों को लाभ मिलेगा। मालवा को नई-नई सड़क परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। सिंहस्थ में 30 से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसी के दृष्टिगत आवागमन की बेहतर सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उज्जैन में शिप्रा के 30 किलोमीटर लंबे स्नान घाटों का निर्माण किया जा रहा है। इंदौर से उज्जैन तक मेट्रो ट्रेन भी जल्द ही आएगी। नई रेलवे लाइनों से नागदा दो रूट से दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग से जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि उज्जैन संभाग देश का मध्य बिंदु है, बहुत जल्द यहां एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात भी मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शहर का भ्रमण दो पहिया वाहन और पैदल चल कर किया

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जलेबी बनाई एवं लिया शाम की चाय का आनंद

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार की शाम उज्जैन पहुंचकर दो पहिया वाहन से एवं पैदल चलकर शहर का भ्रमण कर सिंहस्थ 2028 महापर्व के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव वीआईपी गेस्ट हाउस देवास रोड़ से माधवनगर, टावर चौक होते हुए फ्रीगंज पहुंचे। फ्रीगंज ब्रिज के समानांतर बन रहे नए ब्रिज निर्माण कार्य का अवलोकन किया और सेतु विभाग के अधिकारियों से कार्य की अद्यतन प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कोयला फाटक से कंठाल चौराहे तक चल रहे मार्ग चौडीकरण कार्य का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों से उनकी कुशलक्षेम पूछकर निमार्णाधीन कार्यों के संबंध में चर्चा की। उन्होंने निजातपुरा पहुंचकर वहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कोयला फाटक से निजातपुरा तक पैदल भ्रमण किया और इस दौरान क्षेत्रीय रहवासियों से मिले और उनका अभिवादन स्वीकार किया। रहवासियों ने भी अपने सरल और सहज स्वभाव के मुख्यमंत्री डॉ. यादव को अपने बीच पाकर आत्मीयता के साथ उनका स्वागत किया और अनौपचारिक विषयों पर बातचीत की। कंठाल चौराहे की प्रसिद्ध मिष्ठान्न भंडार की दुकान पर पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दुकान संचालक की कुशलक्षेम पुछी। दुकान संचालक उस समय जलेबी बना रहे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. यादव से जलेबी बनाने का आग्रह किया। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सहजता से उनका आग्रह स्वीकार करते हुए जलेबी बनाई और शाम की चाय का आनंद भी लिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों में से कुछ पूर्ण होने वाले है और कुछ पूर्ण भी हो चुके है। आमजन में विकास कार्यों के प्रति संतोष है। कई कार्यों की काफी समय से आवश्यकता थी, वे प्रगतिरत है। आने वाले समय में निर्माण कार्यों की गति को और तेज किया जाएगा। भगवान श्री महाकालेश्वर की सावन भादौ मास में निकलने वाली सवारी के प्रबंधन पर भी मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों से चर्चा की गई।

भ्रमण में विधायक श्री अनिल जैन कालूहेडा, श्री संजय अग्रवाल, श्री रवि सौलंकी, कलेक्टर श्री रौशन कुमारसिंह, पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

एशियन अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्यप्रदेश के विनोद सिंह ने जीता कांस्य पदक

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के प्रतिभाशाली धावक विनोद सिंह ने चीन के ओरदोस में आयोजित प्रथम एशियन अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में 14:23.67 मिनट का समय निकालकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और मध्यप्रदेश का गौरव बढ़ाया। चैंपियनशिप के 5000 मीटर फाइनल में एशिया के सर्वश्रेष्ठ युवा धावकों के बीच हुई कड़ी प्रतिस्पर्धा में विनोद सिंह ने उत्कृष्ट धैर्य, गति और रणनीति का परिचय देते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। उनका यह प्रदर्शन भारतीय एथलेटिक्स के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है तथा आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भी सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

राजगढ़: गीता ज्ञान से जीवन में शांति और सकारात्मकता का संदेश

यज्ञ में बुराइयों-व्यसनों का किया त्याग

राजगढ़। मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में ब्रह्माकुमारी संस्थान और सोनकच्छ ग्रामवासियों के संयुक्त तत्वावधान में नवनिर्मित सामुदायिक भवन में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भगवद् गीता प्रवचन का समापन शुक्रवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ हुआ।

समापन अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने यज्ञकुंड में अपनी बुराइयों और व्यसनों का प्रतीकात्मक त्याग कर सद्मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। प्रवचनकर्ता ब्रह्माकुमारी सुरेखा दीदी ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में अर्जुन को ज्ञानमय यज्ञ को सर्वोत्तम बताया है। ज्ञान की धारणाएं व्यक्ति के जीवन को यज्ञमय बनाती हैं, जिससे समाज और विश्व में शांति, सुख और पवित्रता का वातावरण निर्मित होता है। उन्होंने आत्मा, परमात्मा, कर्म, राजयोग और जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गीता का ज्ञान जीवन की हर समस्या का समाधान प्रदान करता है तथा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी व्यक्ति को स्थिर और सकारात्मक बनाए रखता है।

जिला प्रभारी बीके मधु दीदी ने कहा कि गीता में बताए गए राजयोग के नियमित अभ्यास से आंतरिक शक्तियों का विकास होता है और व्यक्ति तनाव, दुख व अशांति से सहज मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उन्होंने सभी से आध्यात्मिक जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सोंधिया ने ब्रह्माकुमारी बहनों के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वे अपना जीवन समाजहित और आध्यात्मिक जागरण के लिए समर्पित कर रही हैं, जिसका सभी को सहयोग करना चाहिए। इस अवसर पर सरपंच हरिप्रसाद दांगी एवं ग्राम के गणमान्य नागरिकों ने बीके मधु दीदी, ब्यावरा सेवा केंद्र संचालिका बीके लक्ष्मी, पचोर सेवा केंद्र की बीके वैशाली और बीके सुरेखा दीदी का सम्मान किया। अंत में श्रीमद्भागवत की आरती, भजन-कीर्तन और महाप्रसादी के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। संचालन रामेश्वर दांगी ने किया। कार्यक्रम में आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

प्रदेश में 15 से 30 जुलाई तक चलेगा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान

मप्र सरकार हर प्रकार के नशे पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से 'नशा मुक्त मध्यप्रदेश' अभियान में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार हर प्रकार के नशे पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं से 15 से 30 जुलाई तक मध्य प्रदेश पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को जारी अपने संदेश में कहा है कि मध्य प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस विकास यात्रा में युवा शक्ति रचनात्मक भूमिका निभा रही है। सभी नागरिक भी विकासात्मक गतिविधियों से स्वयं को जोड़कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नशे की प्रवृत्ति समाज की विकास यात्रा पर कुठाराघात करती है। मध्यप्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नशा मुक्त मध्यप्रदेश बनाने के लिए कार्य कर रही है। नशे से लड़ाई में पूरा देश एकजुट है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने हर तरह के नशे पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक अभियान की शुरूआत की है। नशा, नाश की जड़ है, जो वर्तमान और भावी पीढ़ियों को भी बर्बाद कर देता है। नशे से सभी प्रकार की रचनात्मकता और आगे बढ़ने की संभावनाओं पर कुठाराघात होता है, वर्तमान और भविष्य दोनों खराब होते हैं। नशा परिवारों को बर्बाद कर देता है। राज्य सरकार ने अपनी समस्त क्षमताओं के साथ प्रदेशवासियों के सहयोग से नशे के खिलाफ अभियान आरंभ किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में प्रदेशवासियों से 'नशा मुक्त मध्यप्रदेश' अभियान में हरसंभव सहयोग प्रदान करने और अभियान को समर्थन देने का आव्हान किया है।

मध्यप्रदेश राज्य ट्रायथलॉन अकादमी चयन ट्रायल्स में खिलाड़ियों ने दिखाई दमदार प्रतिभा

37 खिलाड़ियों ने तैराकी, साइक्लिंग और रनिंग में दिखाई क्षमता, पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से उभरेंगी नई खेल प्रतिभाएँ

भोपाल। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से टैलेंट सर्च 2026 का आयोजन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य ट्रायथलॉन अकादमी के प्रवेश के लिये चयन ट्रायल्स का सफल आयोजन 6 से 8 जुलाई 2026 तक भोपाल में किया गया। तीन दिवसीय चयन प्रक्रिया टी.टी. नगर स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम बरखेड़ा नाथू तथा प्रकाश तरण पुष्कर में संपन्न हुई, जिसमें खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता, तकनीकी दक्षता एवं सहनशक्ति का व्यापक मूल्यांकन किया गया।

ट्रायथलॉन जैसे चुनौतीपूर्ण खेल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिभागियों का परीक्षण **स्विमिंग, साइक्लिंग, रनिंग, फिजिकल फिटनेस एवं समग्र तकनीकी दक्षता** के विभिन्न मानकों पर किया गया। चयन समिति की निगरानी में पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष एवं निर्धारित मानकों के

अनुरूप संपन्न हुई।

चयन ट्रायल्स में कुल 37 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें 31 बालक एवं 6 बालिका खिलाड़ी शामिल रहे। मध्यप्रदेश के 12 जिलों के साथ उत्तरप्रदेश एवं महाराष्ट्र से भी खिलाड़ियों ने सहभागिता कर प्रतियोगिता को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया। यह सहभागिता प्रदेश की ट्रायथलॉन खेल के प्रति बढ़ती रुचि और विश्वास को दशार्ती है। जिलावार सहभागिता में बुरहानपुर सर्वाधिक 7 खिलाड़ियों के साथ अग्रणी रहा, जिनमें 4 बालिका खिलाड़ी शामिल थीं। इसके अतिरिक्त भोपाल, शिवपुरी, रीवा, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, राजगढ़, सतना, इटारसी एवं बैतूल सहित विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने भी अपनी प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। ट्रायल्स के दौरान अनेक खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट सहनशक्ति, तकनीकी कौशल, अनुशासन एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया। चयन समिति ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को दीर्घकालीन विकास की दृष्टि से सकारात्मक बताते हुए इसे प्रदेश में ट्रायथलॉन खेल के उज्ज्वल भविष्य का संकेत माना।

तीन दिवसीय चयन प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन का अंतिम मूल्यांकन एवं अनुमोदन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों की सूची निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पृथक रूप से जारी की जाएगी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग का उद्देश्य प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, आधुनिक खेल अधोसंरचना एवं विशेषज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करना है।

संपादकः अली आदिल खान द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस डी-85, न्यू अशोक अगर, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी से मुद्रित कराकर सी-148, साउथ मोती वाग,पो. चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 से प्रकाशित किया।
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।